

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 1.4; पृष्ठ: 3)

वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य बजट से बाहर कार्यक्रमों/ योजनाओं के तहत विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्माचन
			2017-18
1.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)	जिला उपायुक्त	4,500.00
2.	बौद्ध और तिब्बती संस्थान और स्मारक	बौद्ध अध्ययन संस्थान	2,315.58
3.	आईएचएमएस/ एफसीआईएस/ आईआईटीएम/ एनआईडब्ल्यूएस आदि की सहायता।	संस्थान और होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी	358.30
4.	सौर ऊर्जा-ऑफ ग्रिड	लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	90.33
5.	शराब और पदार्थ (ड्रग्स) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए योजना।	विधवाओं, अनाथों, विकलांगों और वृद्ध व्यक्तियों (आतंकवाद के शिकार) (आरसीएमवी) के पुनर्वास के लिए परिषद	300.00
6.	सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	संस्थान और होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी श्रीनगर/ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (सोसायटी) जम्मू	188.40
7.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को समर्थन	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग	13,090.00
8.	अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं	मैसर्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग (एनआईटीटी) -(एनआईआईटीजेके)/ ह्यूमन वेल्फेयर ऑर्गनाइजेशन/ हिलाल इंस्टीट्यूट/ सिटीजन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोपोर/ अस्सेंट ग्रुप	105.64
9.	अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों और दिव्यांग छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग	बांदीपोरा सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	106.27
10.	ई-कोर्ट फेज-2	महा पंजीयक, जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट	17,679.54
11.	युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान	85.95
12.	दिव्यांगों के लिए योजना	बांदीपोरा कॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपोजिट रीजनल सेंटर, श्रीनगर/ कश्मीर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड सोलर टेक्नोलॉजी	208.08
13.	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	एसकेयूएसटी जम्मू/ कश्मीर, एसकेआईएमएस/ इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1,147.65
14.	विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	भारतीय समवेत औषध संस्थान, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, एसकेयूएसटी जम्मू/ कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय।	79.52
15.	ईएमआर सहित स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रबंधन	राजकीय मेडिकल कॉलेज, जम्मू	140.00

क्रम सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्माचन
			2017-18
16.	डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	100.00
17.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण आजीविका सोसायटी (जेकेआरएलएस)	659.74
18.	वन स्टॉप सेंटर	उपायुक्त/ ओएससी, जिला कार्यक्रम अधिकारी	87.52
19.	अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच	कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर पर्यावरण और सामाजिक संगठन।	50.50
20.	सीखो और कमाओ-कौशल विकास पहल	मैसर्स नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग (एनआईटीटी) (एनआईआईटीजेके)/ सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग/ टेंड्रल इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ सोफटेक इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ ह्यूमन वेल्फेयर ऑर्गनाइजेशन/ एवरग्रीन इंस्टिट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन	1,324.22
21.	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	357.12
22.	जेएंडके पीएमडीपी अनुदान के तहत पकुल दुल एचईपी के लिए चिनाब वैली पावर को केंद्रीय सहायता।	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड	20,000.00
23.	औद्योगिक बुनियादी ढांचा उन्नयन योजना (आईआईयूस)	राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको), जम्मू एवं कश्मीर	820.50
24.	बुनियादी ढांचा विकास और क्षमता निर्माण	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको)	491.12
25.	नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेएंडके (एसकेयूएसटी-जेएंडके), कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी व्यापार उद्भवन केन्द्र	361.89
26.	कला संस्कृति विकास योजना	जम्मू एवं कश्मीर में विभिन्न सांस्कृतिक और कल्याण समितियां	434.61
27.	खेलों के विकास के लिए खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम	इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आईयूसटी), अवंतिपोरा, पुलवामा, कश्मीर और निदेशक युवा सेवाएं और खेल जम्मू एवं कश्मीर	531.34
28.	भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर भू-अभिलेख प्रबंधन अभिकरण (जेकेएलआरएमए)	477.00
29.	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया को मजबूत करना	इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईएमपीए)/ रीजनल एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर बडगाम।	100.40

क्रम सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्माचन
			2017-18
30.	नई मंजिल- एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल	कॉमटेक प्रौद्योगिकी संस्थान / नेशनल एजुकेशन सोसायटी एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन/ सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग/ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग	479.85
31.	राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर राज्य एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण सोसायटी-[जेकेएसएपीसीएस]	777.04
32.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हरिओम पश्मीना हैंडलूम इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसायटी, जन कल्याण हैंडलूम बुनाई इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, एस्क्वायर रैफल्स पश्मीना हैंडलूम डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड, मैसर्स बादाम पश्मीना और रैफल हैंडलूम डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड, मैसर्स झेलम वैली बेसहारा बुनकर इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मैसर्स शोकिन पश्मीना रैफल और कॉटन हैंडलूम डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड	295.90
33.	खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	इंडो कश्मीर/ कचरू इंडीग्रेटेड कोल्ड चेन/ केसर मसाले और फूड्स/ वाजान फूड्स, सुरक्षित और ताज़ा फूड्स/ शफात ऑयल मिल्स एंड स्पाइस/ मीर एगो इंडस्ट्रीज आदि।	20.29
34.	तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (पीआरएसएडी)	जम्मू एवं कश्मीर स्टेट केबल कार निगम लिमिटेड।	1,152.11
35.	स्मॉल हाइड्रो पावर-ग्रिड इंटरएक्टिव	अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी कारगिल/ जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	1,433.35
36.	नए आईआईएम की स्थापना	भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू।	1,645.00
37.	पारंपरिक उद्योगों के उत्थान हेतु निधि के लिए योजना (एसएफयूआरटीआई)	जम्मू एवं कश्मीर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	430.50
38.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	कश्मीर विश्वविद्यालय/ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय/ भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान/ शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू एवं कश्मीर	1,517.28
39.	अनुसंधान प्रशिक्षण और अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	349.25
40.	अनुसंधान और विकास	जम्मू एवं कश्मीर का शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड रिमोट सेंसिंग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर।	119.42
41.	विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन)	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड/ जम्मू एवं कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड	11,550.08

क्रम सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्माण
			2017-18
42.	विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (यूएसटीडीएडी)	बांदीपोरा सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	82.20
43.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर	2,900.45
44.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	196.75
45.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	उप आयुक्त बीबीबी सांबा, पुलवामा, जिला विकास आयुक्त शोपियां, जिला मजिस्ट्रेट जम्मू, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग आदि।	262.91
46.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी सब्सिडी	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बौद्ध अध्ययन	1,681.64
47.	कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन	जम्मू एवं कश्मीर का शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी / जम्मू एवं कश्मीर स्टेट एग्री इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड।	521.20
48.	नए आईआईटी की स्थापना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू	13,928.00
49.	स्थापना व्यय-आयुष	जम्मू विश्वविद्यालय, स्कुआस कश्मीर, भद्रवाह विकास प्राधिकरण, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोवा-रिग्पा	136.65
50.	परिवार कल्याण योजनाएं	कश्मीर विश्वविद्यालय	84.92
51.	मतदाता शिक्षा	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू एवं कश्मीर	328.75
52.	रोड विंग्स के अंतर्गत निर्माण कार्य	विभिन्न व्यक्तियों और निजी निर्माण कंपनियों	2,681.19
53.	पवन उर्जा- ऑफ ग्रिड	लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	85.72
54.	सीआरएफ से राज्य ईएंडआई को अनुदान	एमजी कान्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड	763.66
55.	अन्य योजनाएं	अन्य योजनाएं	875.80
	कुल		1,10,491.13

(स्रोत: वित्त लेखे 2017-18)

परिशिष्ट-2.1.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.1.8.4; पृष्ठ: 34)

पिछले दो वर्षों के दौरान जिन अधूरे कार्यों के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई, उनको दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	जलापूर्ति योजनाओं का नाम	डिविजन का नाम	प्रारंभ का वर्ष	अनुमानित लागत		खर्च किये		विभाग द्वारा प्रदान किए गए उत्तर का सार
				मूल	संशोधित	वर्ष	राशि	
1.	कन्हेरी	अखनूर	2013-14	40.00	40.00	2014-15	28.75	परित्याग के कारणों की जानकारी मांगी जाएगी और सूचित किया जाएगा।
2.	ट्रिच	अवंतिपोरा	2007-08	184.00	184.00	2012-13	161.10	फंड जारी न करना
3.	बाथन जंट्रग		2003-04	219.00	219.00	2015-16	114.22	स्रोत की कमी
4.	शाह मोहल्ला चोपन बस्ती		2011-12	149.00	149.00	2015-16	86.97	स्रोत से नहीं छोड़ा गया
5.	मारवाल		2007-08	191.00	330.00	2013-14	204.70	पीने योगी नहीं
6.	अमीराबाद चंद्रीगाम		1999-2000	125.00	263.05	2012-13	125.27	बढ़ी हुई लागत
7.	बांडीपोरा बोमाई		सोपोर	2011-12	59.97	59.97	2014-15	10.19
8.	दरदूरा जलूरा	2010-11	61.13	61.13	2013-14	3.28		
9.	हरितार	2008-09	38.00	38.00	2015-16	5.67		
10.	आईआर शर्कवारा	2010-11	200.00	200.00	2015-16	6.55		
11.	फत्तिपोरा चन्देरगिर	2009-10	358.83	358.83	2014-15	344.60		
12.	रख शिल्वत	2010-11	35.95	35.95	2013-14	17.29		
13.	ओडिना में कुआ	2010-11	21.50	21.50	2015-16	47.00		
14.	बोहरिपोरा	2012-13	8.65	8.65	2014-15	2.00		

क्रम सं.	जलापूर्ति योजनाओं का नाम	डिविजन का नाम	प्रारंभ का वर्ष	अनुमानित लागत		खर्च किये		विभाग द्वारा प्रदान किए गए उत्तर का सार
				मूल	संशोधित	वर्ष	राशि	
15.	मोहदफल (जीबी)	बिजबिहारा	2013-14	29.29	29.29	2015-16	22.79	निधि जारी नहीं की गयी
16.	चाकुरा में बांध सह स्पिल वे		2013-14	84.00	84.00	2014-15	96.00	निधि जारी नहीं की गयी
17.	लेस्सू ब्रेन-नाई में आईआर		2010-11	265.00	265.00	2013-14	18.22	निधि जारी नहीं की गयी
18.	अरिगोहाल		2010-11	91.20	91.20	2014-15	60.14	निधि जारी नहीं की गयी
19.	गलबुघ	पुलवामा	2007-08	266.78	366.76	2015-16	263.40	बढ़ी हुई लागत
20.	मिरबघ डौगाम		2009-10	200.00	320.00	2015-16	153.04	बढ़ी हुई लागत
	कुल			2,628.30	3,125.33		1,771.18	

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट-2.1.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.1.8.5; पृष्ठ: 35)

सैंपल डिवीजनों में डीपीआर के बिना क्रियान्वित कार्य

(₹ लाख में)

क्रम सं.	जल आपूर्ति योजना का नाम	डिवीजन का नाम	अनुमानित लागत	मार्च 2013 के अंत तक संचयी व्यय	मार्च 2018 के अंत तक संचयी व्यय	मार्च 2018 के अंत तक वास्तविक स्थिति
1.	कन्हेरी	अखनूर	40.00	0.00	28.75	प्रगति में
2.	श्रोनी जोथल		758.50	0.00	88.91	प्रगति में
3.	बालसरू		71.50	64.50	71.50	पूर्ण
4.	राह/ हरदू मलारा		142.50	1.00	78.36	प्रगति में
5.	पालनवाला (छंब) नलकूप की खुदाई		69.00	41.00	69.00	पूर्ण
6.	रंगपुर चाम्ब नलकूप की खुदाई		77.00	45.00	77.00	पूर्ण
7.	भूम कुलीयन		197.50	105.00	165.75	प्रगति में
8.	जट्टा-दे-कोठे		120.50	2.00	81.79	प्रगति में
9.	जोगवन बरदो		162.00	2.00	44.38	प्रगति में
10.	कोट मकोटे		98.19	95.19	98.19	पूर्ण
11.	देवक	नौशेरा	553.00	8.67	86.87	जारी
12.	चौकी नरियन		305.00	6.90	33.40	जारी
13.	कराल	ग्रामीण जम्मू	93.00	81.88	93.00	पूर्ण
14.	चरंगल		87.00	75.60	87.00	पूर्ण
15.	कहालती		65.40	32.00	65.40	पूर्ण
16.	सिधरा (पुराना)		69.98	34.29	38.29	पूर्ण
17.	मट्टीन		68.31	39.21	68.31	पूर्ण
18.	खदता		69.70	35.90	69.70	पूर्ण
19.	चाकरोज चरण-II		109.52	9.00	88.06	जारी
20.	शुवाड़ा		121.00	33.00	117.50	पूर्ण
21.	डेलनी कसाना		180.00	10.00	119.49	जारी

क्रम सं.	जल आपूर्ति योजना का नाम	डिवीजन का नाम	अनुमानित लागत	मार्च 2013 के अंत तक संचयी व्यय	मार्च 2018 के अंत तक संचयी व्यय	मार्च 2018 के अंत तक वास्तविक स्थिति
22.	वद्वेराबाद	पीएचई बारामूला	225.00	0.00	7.50	जारी
23.	गतियार		224.48	12.89	42.30	जारी
24.	ख्वाजा गुंडी कासिम		366.00	0.00	31.50	जारी
25.	चेक्की सुल्तानपोरा		288.73	225.73	275.60	जारी
26.	रेंज		50.00	0.00	2.00	जारी
27.	फूट पार्क कॉलोनी गुलिगम (सोपोर)		210.00	0.00	5.14	जारी
28.	खोई		756.96	120.54	295.35	जारी
29.	सय्यद कॉलोनी चिनाड		30.00	2.00	30.00	जारी
30.	दन्दूसा डोलिगुंड		92.00	0.00	22.90	जारी
31.	ग्रामीण बारामूला के लिए संयंत्र		75.27	29.97	51.87	जारी
32.	सहकूल गोशुघ		38.00	25.98	26.36	जारी
33.	मलगनिपोरा		144.00	1.81	19.02	जारी
34.	आईआरपी वाटेरगम		48.00	41.12	43.18	जारी
35.	सय्यद कॉलोनी वाबूग		पीएचई सोपोर	24.81	0.00	0.58
36.	रंगी	50.00		0.00	4.59	जारी
37.	शलपोरा तुजार शरीफ	462.00		0.00	29.47	जारी
38.	राखी हयगम हरितार	195.02		0.00	26.90	जारी
39.	फूट पार्क कॉलोनी	210.00		0.00	15.49	जारी
40.	आईआर शर्कवारा	पीएचई सोपोर	200.00	6.25	6.55	जारी
41.	अधल चेर्वाड	पीएचई बिजबिहारा	15.57	4.50	15.57	पूर्ण
42.	नागपथरी चंकितर	पीएचई अवन्तिपोरा	299.13	0.00	31.90	जारी
43.	नेहामा		454.28	0.00	40.62	जारी
	कुल		7,917.85	1,192.93	2,695.04	

क्रम सं.	जल आपूर्ति योजना का नाम	डिवीजन का नाम	अनुमानित लागत	मार्च 2013 के अंत तक संचयी व्यय	मार्च 2018 के अंत तक संचयी व्यय	मार्च 2018 के अंत तक वास्तविक स्थिति
उन योजनाओं का विवरण जहां डीपीआर को ऑडिट करने के लिए नहीं दिखाया गया था						
1	रफता नीमू	लेह	32.10	20.00	32.10	पूर्ण
2	यौलखम		60.30	40.54	60.30	पूर्ण
3	खलसर		40.80	15.00	40.80	पूर्ण
4	उदमरू		43.35	15.00	43.35	पूर्ण
5	साती		52.56	15.00	52.56	पूर्ण
6	बरमा		60.18	46.70	60.18	पूर्ण
7	उरसी डोक		26.80	19.31	26.80	पूर्ण
8	चेग्से डकनक लामायुरु.		33.95	23.00	33.95	पूर्ण
9	जासा बास्गो		249.60	65.00	181.39	प्रगति में
10	कोंचू कोबेट		32.99	0.00	32.99	प्रगति में
11	अगलिंग स्पीतुक		650.80	0.00	65.95	प्रगति में
	कुल		1,283.43	259.55	630.37	

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट-2.1.3

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.1.8.10; पृष्ठ: 42)

भूमि अधिग्रहण/ स्रोत विकास आदि के बिना आरंभ की गई जलापूर्ति योजनाओं का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	जल आपूर्ति योजना का नाम	डिवीजन का नाम	प्रारम्भ करने की तिथि	पूर्ण होने की परिकल्पित तिथि	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय	जिस वर्ष तक व्यय हुआ	निष्फल व्यय के कारण	अनंतिम स्थिति	डिवीजनों द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सार
1.	दत्रीयाल	ग्रामीण जम्मू	2012-13	2014-15	275.90	83.99	2017-18	भूमि के गैर-अधिग्रहण के कारण वितरण ओएचटी के बिना पूरा हुआ	जारी	ट्यूबवेल तथा ओएचटी के लिए चयनित भूमि न्यायाधीन थी।
2.	बेरमीनी		2011-12	2013-14	401.65	199.16	2017-18	ट्यूबवेल से पानी का अपर्याप्त प्रवाह	जारी	पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता
3.	जमोतियान कोगरखू	अखनूर जम्मू	2010-11	2011-12	149.78	106.34	2017-18	स्रोत विकास के बिना वितरण पूरा हुआ।	जारी	सीजीडब्ल्यूबी ने डब्ल्यूएसएस के लिए अलग-अलग स्रोत रखे हैं
4.	मावा चेरियन		2010-11	2012-13	126.38	67.97	2017-18	स्रोत विकास के बिना वितरण पूरा हुआ।	जारी	ट्यूबवेल की विफलता के बाद, सीजीडब्ल्यूबी ने कुआं खोदने के लिए सलाह दी है
5.	बस्ती जोगियाँ मोहल्ला	शहर-II जम्मू	2011-12	2013-14	190.00	163.26	2017-18	भूस्वामियों के बीच स्रोत विवाद	जारी	भूस्वामियों के बीच विवाद
6.	संत रोचा सिंह		2012-13	2014-15	229.61	49.62	2016-17	भूस्वामियों के बीच स्रोत विवाद	जारी	भूस्वामियों के बीच विवाद

क्रम सं.	जल आपूर्ति योजना का नाम	डिवीजन का नाम	प्रारम्भ करने की तिथि	पूर्ण होने की परिकल्पित तिथि	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय	जिस वर्ष तक व्यय हुआ	निष्फल व्यय के कारण	अंतिम स्थिति	डिवीजनों द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सार
7.	कठुआ औद्योगिक इस्टेट	पीएचई डिवीजन कठुआ	2006-07	2008-09	161.25	119.79	2017-18	ओएचटी के बिना वितरण पूर्ण हुआ	जारी	धन की अनुपलब्धता के कारण डबल्यूएसएस पूरा नहीं हुआ
8.	बारी दरहल	पीएचई डिवीजन राजौरी	2008-09	2011-12	374.70	138.26	2017-18	11 वर्ष बीत जाने के बाद भी एलएफ/ डीएस पूरा नहीं हुआ	जारी	पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता
9.	टोपा डोडज		2007-08	2010-11	399.00	154.20	2017-18	इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन और पंप मशीनरी	जारी	पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता
10.	जुंगरियाल	पीएचई नौशेरा	2011-12	2014-15	271.30	100.60	2017-18	स्रोत विकास, पंपिंग स्टेशन जैसे यांत्रिक भाग को पूरा नहीं किया गया था	जारी	अल्प धन के कारण स्रोत पूरा नहीं हो सका
11.	बेरी पट्टन		2010-11	2013-14	179.48	153.13	2017-18	योजना का स्रोत और निस्पंदन संयंत्र पूरा नहीं हुआ	जारी	धन की अल्पता के कारण योजना पूर्ण नहीं हो सकी।
12.	नीमू	पीएचई लेह	2012-13	2014-15	399.00	282.58	2017-18	पम्पिंग मशीनरी की गैर-स्थापना	जारी	धन की अनुपलब्धता के कारण पूर्ण नहीं हो सका
13.	जहामा	पीएचई बारामूला	2007-08	2010-11	354.00	284.47	2017-18	वितरण नेटवर्क के न बिछाने और फिटिंग तथा अतिरिक्त कच्चे पानी के सह-पंप हाउस का निर्माण नहीं करना	जारी	योजना को चालू वर्ष में पूरा किया जाएगा जोकि उच्च अधिकारियों से प्राप्त धन के अधीन है

क्रम सं.	जल आपूर्ति योजना का नाम	डिवीजन का नाम	प्रारम्भ करने की तिथि	पूर्ण होने की परिकल्पित तिथि	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय	जिस वर्ष तक व्यय हुआ	निष्फल व्यय के कारण	अंतिम स्थिति	डिवीजनों द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सार
14.	भट मोहल्ला सांगी गुजरपटी	पीएचई सोपोर	2012-13	2015-16	348.25	217.17	2017-18	स्रोत विवाद	जारी	स्रोत विवाद
15.	खुशालपोरा सय्यद कॉलोनी संग्रामा		2012-13	2015-16	690.82	164.32	2017-18	स्रोत साइट के गलत चयन का परिणाम दूषित पानी निकलना।	कार्य रोका गया	पानी पीने योगी नहीं
16.	शाह मोहल्ला पंजीनारा		2012-13	2015-16	402.14	158.40	2017-18	स्रोत विवाद	कार्य रोका गया	स्रोत विवाद
17.	शिवा-जैनागीर		2012-13	2015-16	309.00	347.68	2017-18	स्रोत विवाद मामले के न्यायाधीन होने के कारण 150 मिमी व्यास फीडिंग मेन की बिछाने और फिटिंग को क्रियान्वित नहीं किया जा सका	कार्य रोका गया	स्रोत विवाद
18.	सईदापोरा-दंगरपोरा		2011-12	2013-14	816.00	367.07	2017-18	भूमि विवाद मामला न्यायाधीन	विवाद के कारण कार्य रोका गया	न्यायाधीन
19.	निगली घाट		2013-14	2015-16	294.43	112.57	2015-16	वन विभाग से एनओसी प्राप्त नहीं करना	अवरुद्ध कार्य एनओसी प्राप्त करने के पश्चात शुरू किया जाएगा	एनओसी जारी करने हेतु मामला वन विभाग के साथ उठाया गया है

क्रम सं.	जल आपूर्ति योजना का नाम	डिवीजन का नाम	प्रारम्भ करने की तिथि	पूर्ण होने की परिकल्पित तिथि	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय	जिस वर्ष तक व्यय हुआ	निष्फल व्यय के कारण	अंतिम स्थिति	डिवीजनों द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सार
20.	अशाम बोनपोरा जूनीपोरा		2011-12	2013-14	234.37	195.00	2017-18	डीपीआर में डीआई पाइप 200 मिमी व्यास राइसिंग मेन बिछाने और फिटिंग का गैर-निगमन	जारी	मूल डीपीआर के तहत गैर-निगमन घटक
21.	अलसफ़ा कॉलोनी	पीएचई यांत्रिक (उत्तर) सोपोर	2011-12	2013-14	195.00	167.24	2016-17	डबल्यूएसएस के सफल कमीशन के लिए आवश्यक उपकरणों/वर्क्स को मूल डीपीआर के दायरे में शामिल नहीं किया गया था	जारी	कुछ कार्य मूल अनुमानों के अंतर्गत नहीं हैं जोकि सफल कमीशन के लिए आवश्यक हैं
22.	शेखपोरा अनन्वान		2012-13	2014-15	32.50	20.75	2017-18	भूमि विवाद के कारण सिविल कार्य अपूर्ण	जारी	भूमि विवाद
23.	बुमहमा		2011-12	2014-15	109.00	69.31	2017-18	भूस्वामियों के साथ विवाद	जारी	भूमि विवाद
24.	दडचेक में आईआर संयंत्र		2012-13	2014-15	84.00	37.00	2017-18	भूमि विवाद	कार्य रोका गया	भूमि विवाद
25.	राइटेंगीरी	पीएचई बिज्बिहेड़ा	2012-13	2014-15	115.00	115.00	2017-18	निस्पंदन प्लांट के पूरा न होने के कारण योजना पूर्ण हैं परंतु क्रियाशील नहीं है	पूर्ण परंतु क्रियाशील नहीं	इसे क्रियाशील बनाने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है
26.	मस्खुड	पीएचई काजीगुंड	2008-09	2010-11	159.41	154.97	उपलब्ध नहीं	वितरण नेटवर्क के लिए पाइप के न बिछाने और फिटिंग न होने के कारण स्रोत कम हो गया -	जारी	स्रोत कम हो गया

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्र

क्रम सं.	जल आपूर्ति योजना का नाम	डिवीजन का नाम	प्रारम्भ करने की तिथि	पूर्ण होने की परिकल्पित तिथि	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय	जिस वर्ष तक व्यय हुआ	निष्फल व्यय के कारण	अंतिम स्थिति	डिवीजनों द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सार
27.	अतिरिक्त ओएचटी गस्सीपोरा का निर्माण		2013-14	2015-16	69.75	64.22	उपलब्ध नहीं	पानी की गुणवत्ता की समस्या के कारण योजना को चालू नहीं किया जा सका क्योंकि डीपीआर में निस्पंदन संयंत्र निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया था	जारी	जल गुणवत्ता समस्या
28.	गल्लेण्डर	पीएचई अवन्तिपोरा	2007-08	2010-11	195.50	250.80	2017-18	लागत अधिक होने के कारण न तो योजना पूरी नहीं हो सकी और न चालू हो सकी	बढ़ी हुई लागत	बढ़ी हुई लागत
	कुल				7,567.22	4,344.87				

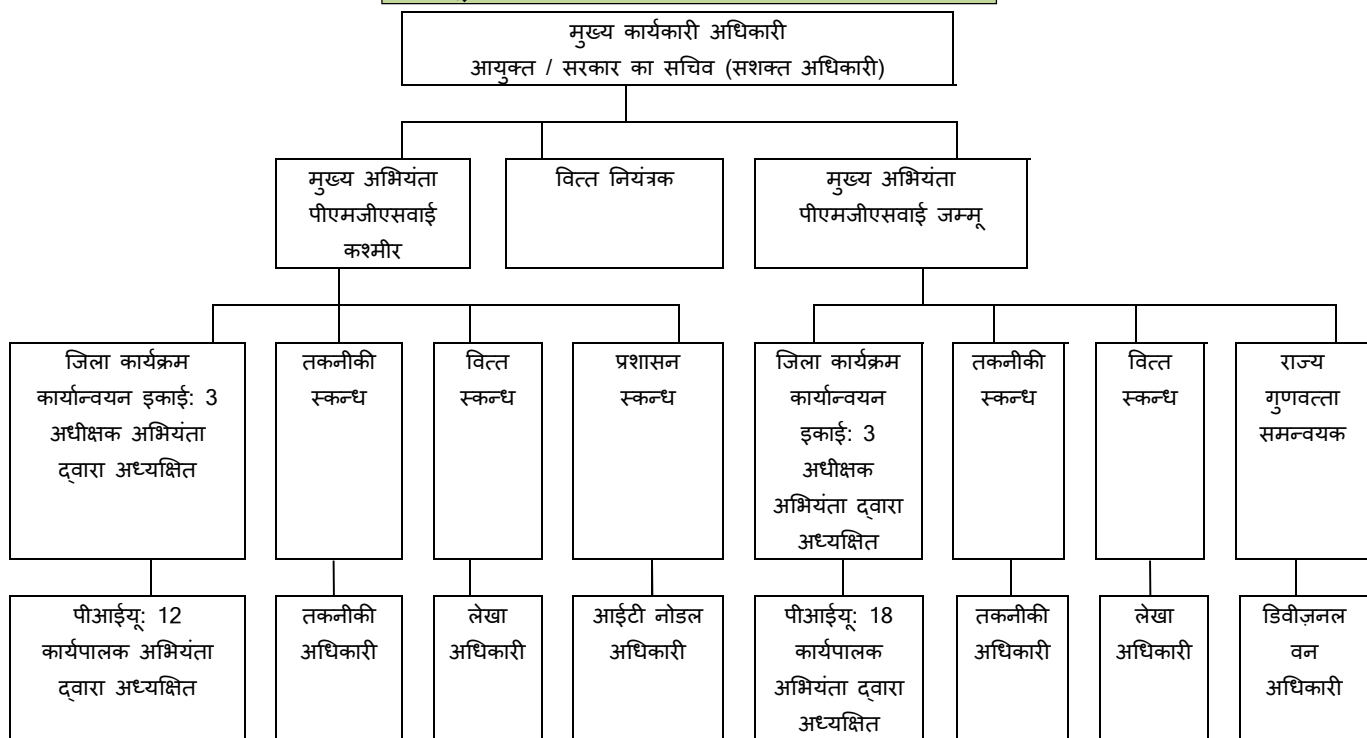
(स्रोत : नमूनित डिवीजनों में डब्ल्यूएसएस की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट-2.2.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.2 एवं 2.2.4; पृष्ठ: 54 और 57)

संगठनात्मक ढांचा और लेखापरीक्षा के मापदंड

जम्मू एवं कश्मीर राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी



(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना)

लेखापरीक्षा के मापदंड

1. जिला ग्रामीण पथ योजना (डीआरआरपी), कोर नेटवर्क, सीएनसीपीएल और सीयूपीएल;
2. पीएमजीएसवाई की संचालन नियमावली और मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के उपबंध;
3. जम्मू और कश्मीर लोक कार्य संहिता और समय-समय पर निर्गत आदेश; और
4. गुणवत्ता नियंत्रण और अनुश्रवण प्रणाली।

परिशिष्ट-2.2.2

(संदर्भ पैराग्राफ:2.2.4; पृष्ठ: 56)

सड़क परियोजनाओं की स्थिति

(सड़क परियोजनाएं/ बस्तियां संख्या में, लंबाई कि.मी. में तथा लागत ₹ करोड़ में)

विवरण		वर्ष वार ब्योरा					कुल
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2013-18
लंबाई और बस्तियां सहित संस्वीकृत सड़क परियोजनाएं जो कि वर्ष की शुरुआत में जुड़े हुए नहीं थे	सड़क परियोजनाएं	1,227	1,022	845	681	1,126	-
	लंबाई	5,863.13	4,971.34	4,036.68	3,548.57	6,639.91	-
	बस्तियां	749	560	428	343	851	-
	लागत	3,289.30	2,755.13	2,332.40	2,074.01	4,619.77	-
वर्ष के दौरान लंबाई तथा बस्तियां सहित संस्वीकृत सड़क परियोजनाएं	सड़क परियोजनाएं	0	0	0	542	0	542
	लंबाई	0	0	0	3,519.94	0	3,519.94
	बस्तियां	0	0	0	595	0	595
	संस्वीकृत लागत	0	0	0	2,842.32	0	2,842.32
जोड़ने हेतु लंबाई तथा बस्तियां सहित कुल सड़क परियोजनाएं	सड़क परियोजनाएँ	1,227	1,022	845	1,223	1,126	-
	लंबाई	5,863.13	4,971.34	4,036.68	7,068.51	6,639.91	-
	बस्तियां	749	560	428	938	851	-
	लागत	3,289.30	2,755.13	2,332.40	4,916.33	4,619.77	-
लंबाई तथा बस्तियां की सहित जोड़ी गई कुल सड़क परियोजनाएं	सड़क परियोजनाएं	205	177	164	97	167	810
	लंबाई	891.79	934.66	488.11	428.60	1,429.34	4,172.50
	बस्तियां	189	132	85	87	226	
	लागत	534.17	422.73	258.39	296.56	709.44	
पूर्ण की गई सड़क परियोजनाएं (प्रतिशत में)		17	17	19	8	15	
वर्ष के अंत में लंबाई तथा बस्तियां सहित बिना जुड़ी हुई सड़क परियोजनाएँ	सड़क परियोजनाएं	1,022	845	681	1,126	959	
	लंबाई	4,971.34	4,036.68	3,548.57	6,639.91	5,210.57	
	बस्तियां	560	428	343	851	625	
	लागत	2,755.13	2,332.40	2,074.01	4,619.77	3,910.33	

(स्रोत: जेकेएसआरआरडीए के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.2.3

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.4; पृष्ठ: 57)

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु नमूना-चयन

जिले का नाम	कुल पैकेज					चयनित पैकेज				
	सड़क परियोजनाओं की संख्या	निष्पादन लेखापरीक्षा से पूर्व जारी सड़क निर्माण कार्य	निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संस्वीकृत सड़क निर्माण कार्य	पूर्ण किए गए सड़क निर्माण कार्य	जारी सड़क निर्माण कार्य	सड़क परियोजनाओं की संख्या	निष्पादन लेखापरीक्षा से पूर्व जारी सड़क निर्माण कार्य	निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संस्वीकृत सड़क निर्माण कार्य	पूर्ण किए गए सड़क निर्माण कार्य	जारी सड़क निर्माण कार्य
नए संबद्ध निर्माण कार्य										
रामबन	77	65	12	22	55	20	17	3	5	15
राजौरी	166	105	61	74	92	42	26	16	18	24
उधमपुर	280	237	43	91	189	70	57	13	26	44
जम्मू	53	34	19	31	22	14	9	5	7	7
बारामूला	75	49	26	22	53	19	15	4	5	14
गांदरबल	67	55	12	23	44	17	16	1	6	11
कुपवाड़ा	69	60	9	46	23	18	17	1	15	3
अनंतनाग	110	87	23	59	51	28	20	8	16	12
लेह	10	10	0	6	4	5	5	0	3	2
कुल	907	702	205	374	533	233	182	51	101	132
उन्नयन निर्माण कार्य										
रामबन	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
राजौरी	10	4	6	4	6	5	4	1	4	1

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्र

जिले का नाम	कुल पैकेज					चयनित पैकेज				
	सड़क परियोजनाओं की संख्या	निष्पादन लेखापरीक्षा से पूर्व जारी सड़क निर्माण कार्य	निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संस्वीकृत सड़क निर्माण कार्य	पूर्ण किए गए सड़क निर्माण कार्य	जारी सड़क निर्माण कार्य	सड़क परियोजनाओं की संख्या	निष्पादन लेखापरीक्षा से पूर्व जारी सड़क निर्माण कार्य	निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संस्वीकृत सड़क निर्माण कार्य	पूर्ण किए गए सड़क निर्माण कार्य	जारी सड़क निर्माण कार्य
उधमपुर	5	0	5	0	5	5	0	5	0	5
जम्मू	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4
बारामूला	12	0	12	0	12	5	0	5	0	5
गांदरबल	4	2	2	2	2	4	2	2	2	2
कुपवाड़ा	24	12	12	11	13	6	4	2	4	2
अनंतनाग	8	2	6	3	5	5	2	3	3	2
लेह	4	1	3	0	4	4	1	3	0	4
कुल	72	21	51	20	52	39	13	26	13	26
कुल योग	979	723	256	394	585	272*	195	77	114	158

(*272 नमूनित सड़क परियोजनाओं में से, 18 सड़क परियोजनाएं सैंपलिंग के समय निविदा/ गैर-आबंटन के अधीन थीं तथा, इस प्रकार विस्तृत संवीक्षा हेतु विचार नहीं किया गया)

परिशिष्ट-2.2.4

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.6.2 (ख); पृष्ठ: 73)

विभागीय प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से प्रत्यक्ष निरीक्षित की गई सड़कों की सूची

क्रम सं.	जिला	कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई	चरण-I				चरण-II	
			पैकेज संख्या/ फेज	सड़क का नाम	पूर्ण होने की तिथि	व्यय	पैकेज संख्या/ फेज	स्थिति
1	उधमपुर	उधमपुर	जेके14- 153/ VII	मौड़ से पट्टियान से ऊपरी मौड़	दिसंबर 2012	266.81	316/ VIII	एनए (आबंटित नहीं)
2	उधमपुर	उधमपुर	जेके14- 411/X	मानसर से सौराप	नवंबर 2017	278.98		एनए
3	उधमपुर	रामनगर	जेके14-21/ V	प्लासीयन से पिंगर	मई 2017	280.84	242/ VIII	एनए
4	उधमपुर	रामनगर	जेके14-158/ VII	सुनेटर खास से धनवाल्ड	जून 2013	490.69	351/ VIII	एनए
5	उधमपुर	रामनगर	जेके14-149/ VII	डूडु से गुरातास	मार्च 2017	252.82	344/ VIII	एनए
6	उधमपुर	रामनगर	जेके14-154/ VII	जखेड़ से गुरशलला	मई 2017	93.10	324/ VIII	एनए
7	रामबन	रामबन	जेके14-54/ VI	मावेयल कोटे सुंददा ठैठारका	सितंबर 2016	215.43	367/ VIII	एनए
8	रामबन	रामबन	जेके14-42/ VI	पर्यमुल्ला तुंगीयन जब्बर	अक्टूबर 2013	190.56	368/ VIII	एनए
9	रामबन	बनिहाल	जेके04-68/ VI	बीबी रामसू अदमार्ग से माहो	पूर्ण	445.05	452/ XI	एनए
10	राजौरी	राजौरी	जेके12-16/ V	राजधानी से पंजगैन	मई 2013	422.89	221/ X	निविदा के अधीन (यूटी)
11	राजौरी	राजौरी	जेके12-42/ VI	डूंगी से नाम्बलन	दिसंबर 2013	146.13	208/ X	यूटी
12	लेह	लेह	जेके09-03	हुंडर से हुंडर डोंक	दिसंबर 2013	195.16	एनए	एनए

(स्रोत: पीआईड्यू के वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट-2.2.5

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.8; पृष्ठ: 81)

विभिन्न कारणों से राज्य में रुकी हुई सड़क परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं.	पीआईयू का नाम	सड़क परियोजना का नाम	पैकेज संख्या	चरण	फेज	लंबाई कि.मी. में	संस्वीकृत लागत (₹ लाख में)	जनवरी 2018 तक व्यय (₹ लाख में)	संबद्ध होने वाली बस्तियों की संख्या	अभ्युक्तियाँ
जम्मू प्रांत										
1	माहोर	भाल्ल से शिब्रास्त	जेके14-43	I	VI	9.06	712.14	391.14	1	5वें कि.मी. में पुल के ऊपर सीडी/ संरक्षण कार्य रुके हुए हैं क्योंकि पुल स्वीकृत पैकेज में शामिल नहीं है।
2	बिलावर	नान-गल्ला से ट्राप्पर	जेके07-25	I	VI	1.58	74.78	21.13	3	माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के कारण निर्माण कार्य अक्टूबर 2012 से रुका हुआ है।
3	बनिहाल	हेवागन से धंमस्ता	जेके04-99	I	VI	9.20	628.06	255.11	1	टेक ऑफ पॉइंट बदला गया, एनआरआरडीए को अनुमोदन हेतु संशोधित प्रस्ताव भेजा गया था।
4	माहोर	चिताबस से सिलधार	जेके14-136	I	VII	6.00	353.20	248.24	1	ठेकेदार द्वारा कार्य रोका गया, प्रिंट मीडिया द्वारा अंतिम नोटिस भेजा गया।
5	डोडा	खेल्लानी द्रांगा हुड से सरस	जेके04-114	I	VII	11.82	698.58	135.92	4	नई संयुक्त जांच संचालित की गई, मामला सीसीएफ को भेजा गया, कार्य अवरुद्ध है।
6	रामबन	बटोत से चकवाह तक सड़क	जेके04-133	I	VII	10.00	829.26	149.04	6	वन निर्बाधन प्रतीक्षित
7	उधमपुर	सिरा से घरी	जेके14-155	I	VII	5.02	261.83	218.74	1	योजना वन्य जीवन भाग में 1 आरडी-500-1000 में रुकी हुई है।
8	माहोर	लेंचा हरीवाला	जेके14-140	I	VII	10.00	721.97	346.32	2	वन संस्वीकृति प्रतीक्षित
9	रामबन	ढाड़नों से पप्रयाह	जेके04-131	I	VII	6.00	352.70	0.34	1	वन संस्वीकृति प्रतीक्षित
10	उधमपुर	चौकी से खुरकल	जेके14-112	I	VII	9.05	374.84	290.24	2	माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है

क्रम सं	पीआईयू का नाम	सड़क परियोजना का नाम	पैकेज संख्या	चरण	फेज	लंबाई कि.मी. में	संस्वीकृत लागत (₹ लाख में)	जनवरी 2018 तक व्यय (₹ लाख में)	संबद्ध होने वाली बस्तियों की संख्या	अभ्युक्तियाँ
11	माहोर	अरनस से चीलड़	जेके14-139	I	VII	11.00	684.76	145.70	1	संस्वीकृत लंबाई 11 कि.मी. में से अर्धवर्क 3.900 किमी तक पूर्ण हुआ। मामला माननीय अधीनस्थ न्यायालय, रेयासी में ट्राइल के अधीन है।
12	माहोर	चकलस्स से धारियन	जेके14-188	I	VII	5.50	383.66	103.78	1	संरचना प्रतीकर लंबित
13	रामबन	खूंगा से कोठी जागीर	जेके04-135	I	VIII	9.20	384.30	258.74	2	5 वे कि.मी. से आगे वन मंजूरी न मिलने के कारण रुका हुआ
14	ठाठरी	ठलोरम से समी	जेके04-150	I	VIII	6.37	435.20	314.42	1	मामला वन विभाग को भेजा गया तथा सीसीएफ के पास एफएसी को आगे भेजने हेतु पड़ा है।
15	रामनगर	चाराल से नप्पाह	जेके14-166	I	VIII	9.90	522.11	245.60	1	वन मंजूरी न मिलने के कारण योजना को 7.2 किमी से परे 9.2 किमी के आगे रोका जाना।
16	जम्मू	कहपोता से अप्पर स्ले	जेके05-99	II	VIII	2.23	66.19	20.07	0	भूमि अधिग्रहण तथा टेक ऑफ प्लांट में निजी संरचना के कारण कार्य रोका गया।
17	बुधल	एल025 से नरला	जेके12-164	I एवं II	IX	12.00	1,261.01	171.29	2	वन संस्वीकृति प्राप्त की गई, कार्य शुरू किया जाना है
कश्मीर प्रांत										
18	अनंतनाग	रीन चौगुंड से कूट गुज्जर बस्ती	जेके01-122	I	VII	3.0	116.55	0	1	वन मंजूरी लंबित
19	अनंतनाग	रीन चौगुंड से कूट गुज्जर बस्ती	जेके01-251	II	VIII	3.0	162.51	0	0	वन मंजूरी लंबित
20	अनंतनाग	एल032 से मसवाई	जेके01-267	I	X	2.3	168.77	20.47	1	वन मंजूरी लंबित
21	अनंतनाग	विलू से बोंकाह	जेके01-291	I	X	1.5	112.45	0	1	संरक्षण विवाद
22	अनंतनाग	देस्सू से गोगनाई	जेके01-112	I	VII	3.0	175.62	91.76	1	भूमि विवाद
23	अनंतनाग	देस्सू से गोगनाई	जेके01-244	II	VIII	3.00	119.40	0	0	भूमि विवाद
24	बांदीपोरा	नेरू से सिकंदर	जेके03-72	I	VII	6.7	470.90	392.10	2	वन मंजूरी लंबित
25	बांदीपोरा	एल02 से सफाड़ आब	जेके03-160	I	X	3.5	274.70	0	1	वन मंजूरी लंबित
26	बांदीपोरा	पुराना टेलीहाल से दांगीठाल	जेके03-161	I	X	2.0	172.26	39.11	2	वन मंजूरी लंबित

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्र

क्रम सं	पीआईयू का नाम	सड़क परियोजना का नाम	पैकेज संख्या	चरण	फेज	लंबाई कि.मी. में	संस्वीकृत लागत (₹ लाख में)	जनवरी 2018 तक व्यय (₹ लाख में)	संबद्ध होने वाली बस्तियों की संख्या	अभ्युक्तियाँ
27	बांदीपोरा	डावर टेलीहाल रोड काशपोत से रेफूजी	जेके03-162	I	X	11.0	939.79	0	4	वन मंजूरी लंबित
28	बांदीपोरा	गुजरां से अब्दुल्लियाँ	जेके03-163	I	X	3.5	328.39	0	1	संरक्षण का स्थानांतरण
29	बांदीपोरा	पीर बूथो से चंदाजी	जेके03-155	I	X	6.0	689.90	0	1	वन मंजूरी लंबित
30	बांदीपोरा	अठवाटू वेवन से लबकचेल	जेके03-164	I	X	14.0	975.06	0	3	वन मंजूरी लंबित
31	उरी	डाकेन से गनी मोहल्ला	जेके03-168	I	X	4.0	331.96	0	1	संरक्षण/ भूमि विवाद
32	उरी	सुल्तान ढाकी से धानीमार	जेके03-170	I	X	3.4	300.25	0	1	संरक्षण विवाद
33	उरी	चंदनवाड़ी से चंदनवाड़ी बाला	जेके03-176	I	X	3.0	273.28	82.11	1	वन मंजूरी लंबित
34	गांदरबल	एनएचडबल्यू- गगनजीमर्ड	जेके13-50	I	VII	2.0	126.78	0	3	बस्तियाँ संबद्ध
35	गांदरबल	थुने से बढी पथरी	जेके13-49	I	VII	8.0	573.74	0	2	न्यायालय का स्टे/ वन मंजूरी लंबित
36	गांदरबल	एनएचडबल्यू से गुजरपट्टी द्वितीय	जेके13-106	I	X	1.5	100.71	0.35	1	भूमि अधिग्रहण लंबित
37	गांदरबल	एल042 से शेखपोरा	जेके13-109	I	X	1.9	112.75	0.44	1	भूमि विवाद
38	गांदरबल	एनएचडबल्यू से गिचखुद	जेके13-111	I	X	5.6	435.02	1.23	1	भूमि अधिग्रहण लंबित
39	गांदरबल	सुमबलबल से छेकिगुंड	जेके13-115	I	X	3.0	250.04	32.45	1	भूमि समस्या
40	गांदरबल	एलएसबी सुमबलबल से छेकिगुंड	जेके13-119	एल एसबी	X		323.61	14.26	0	भूमि समस्या
41	श्रीनगर	एल034 से न्यूठीड मुल्हर	जेके13-108	I	X	3.2	78.28	0	1	भूमि विवाद
42	कुलगाम	रेडवानी से रामपोरा	जेके01-301	I	X	1.76	111.43	0	1	भूमि प्रतिकर
43	कुलगाम	एचपी तवल्ला से राखी हसनपोरा	जेके01-302	I	X	1.75	92.43	0	1	भूमि प्रतिकर
44	बडगाम	एल040 डुडरू से नौगाम	जेके02-85	I	X	1.87	254.38	0	1	वन मंजूरी लंबित
45	कारगिल	एल/ आर शकर सफी	जेके06-16	I एवं II	VI	3.0	49.52	2.52	1	भूमि विवाद
46	पुलवामा	नाइरा से चेक नाइरा	जेके10-152	I	X	1.5	103.24	0	1	भूमि विवाद
	कुल						16,968.31	3,992.62	66	

(स्रोत: पीएमजीएसवाई जम्मू/ श्रीनगर, मुख्य अभियंता की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट-2.2.6

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.8.5; पृष्ठ: 86)

लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अन्य प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यकता	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	विभाग का उत्तर
1.	प्रशासनिक अनुमोदन/ तकनीकी संस्वीकृति का न मिलना	एमओआरडी, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों की मंजूरी का मिलना यह संकेत नहीं देता है कि प्रशासनिक प्रस्ताव (एए) या तकनीकी स्वीकृति (टीएस) मिल गई है बल्कि इस संबंध में राज्य सरकार को भी ऐसी प्रक्रिया अपनानी होती है। (कार्यक्रम दिशा निर्देश का पैरा 10.2)	नौ नमूना जिलों में 254 सड़क परियोजनाएँ, ₹1,031.35 करोड़ की लागत से संस्वीकृत की गई थी, जिस पर ₹514.62 करोड़ का व्यय किया गया था, जो प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी संस्वीकृति के बिना ₹935.96 करोड़ की लागत पर आवंटित की गई थी।	ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि सड़क परियोजनाएं एसटीए, एसएलएससी और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं और अलग-अलग एए/ टीएस की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, निर्देशों को अनुपालन हेतु नोट किया गया है
2.	निविदाएँ आमंत्रित करने में अनियमितताएँ	मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। (पीएमजीएसवाई के ओएम का पैरा 7.11)	लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई 272 सड़क परियोजनाओं में से 77 सड़क परियोजनाओं ¹ के लिए निविदाएं मंत्रालय द्वारा अनुमोदन की तारीख से 3 दिन से 5 वर्ष और 11 महीनों ² के बीच विलंब से आमंत्रित की गई।	मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई कश्मीर ने (जुलाई 2018 में) कहा कि भारत सरकार द्वारा योजनाओं को मंजूरी दिए जाने के बाद निविदाओं को तुरंत आमंत्रित किया गया था। हालांकि, चरण-I के तहत स्वीकृत सड़क परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण, चरण-II कार्यों के लिए निविदाओं के आमंत्रण में देरी हुई। इसके अतिरिक्त, अदालती मामलें, भूमि विवाद, वन मंजूरी आदि जैसे बाधाओं को देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

¹ जम्मू: 59; कश्मीर: 18

² बलहामा से ब्रामण तक पैकेज संख्या जेके 03-08 के तहत सड़क को एनआरआरडीए द्वारा जून 2004 में संस्वीकृति दी गई थी, जबकि एनआईटी को पीआईयू बरामूला द्वारा अप्रैल 2010 में आमंत्रित किया गया था

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	दिशा निदेशों के अनुसार आवश्यकता	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	विभाग का उत्तर
3.	कार्य आबंटन/प्रदान करने में देरी	पीएमजीएसवाई दिशानिर्देश (पैरा 13.2) में निर्दिष्ट है कि औसत निविदा समय 75 दिन है अर्थात् इसी समय सीमा के भीतर एनआरआरडीए द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन की तारीख से ही कार्यों को प्रदान किया जाना है। टेंडर को अंतिम रूप देने और काम को प्रदान किए जाने को 71 दिनों (पुनः निविदा के मामले में 120 दिन) के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। (ओएम का पैरा 8.1.2)	जम्मू प्रांत में, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चरण-II के तहत 76 सड़क परियोजनाओं ³ में से, ₹121.02 करोड़ की संस्वीकृत लागत के साथ 30 सड़क परियोजनाओं को निविदा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। चूंकि इन सड़क परियोजनाओं का चरण-I अभी भी अपूर्ण था और शेष ₹154.31 करोड़ की संस्वीकृत लागत वाली 46 सड़क परियोजनाएं निविदाओं की प्रतिक्रिया में अभाव के कारण प्रदान नहीं की जा सकीं। इन सड़क परियोजनाओं के चरण-II के लिए एमओआरडी से मंजूरी प्राप्त करने से पहले चरण-I को पूरा किया जाना सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता और मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद भी 60 से 65 महीने तक इन सड़क परियोजनाओं को प्रदान नहीं किया जाना एक खराब योजना का संकेत था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 148 सड़कों की परियोजनाओं (जम्मू: 96; कश्मीर: 52) की बोली प्रक्रिया को पूरा करने में 3 दिन से 2 साल और 8 महीने के बीच देरी हुई थी और नौ मामलों में, निविदाओं की पहली कॉल का विवरण अभिलेखों में नहीं था (फरवरी 2018)।	
4.	बीमा कवर का प्रावधान न किया जाना	ठेकेदार अपनी लागत से दोष देयता अवधि शुरू होने की तारीख से लेकर अंत तक उपकरणों, संपत्ति और व्यक्तिगत चोट या ठेकेदारों के जोखिम के कारण होने वाली क्षति के नुकसान के लिए इंश्योरेंस कवर प्रदान करेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट ठेकेदार द्वारा प्रारम्भ होने की तिथि से पहले अनुमोदन के लिए संबंधित अभियंता को भेजे जाएंगे। (ओएम के पैरा 9.3.1 और अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 13)	नौ नमूना जिलों में 254 सड़क परियोजनाएं, ₹1,031.35 करोड़ की लागत से स्वीकृत की गई थी, जिस पर वर्ष 2013-18 के दौरान ₹514.62 करोड़ का व्यय किया गया था, ठेकेदारों से कोई भी बीमा पॉलिसी और प्रमाण पत्र लिए बिना उन्हें ₹935.96 करोड़ की लागत से ठेका दे दिया गया था।	ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि बीमा कवर से संबन्धित मामलों को ठेकेदारों के साथ कार्य शुरू होने से पहले उठाया जाएगा।

³ जुलाई 2012 में चरण-VIII: 59; दिसंबर 2012 में चरण-IX: 17

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	दिशा निदेशों के अनुसार आवश्यकता	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	विभाग का उत्तर
5.	मोबिलाइजेशन और उपकरण अग्रिम की वसूली न होना	कार्य आदेश जारी होने की तारीख के पश्चात 10 दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा श्रमिक, सामग्री और मशीनरी को जुटाना आवश्यक है। (ओएम का पैरा 9.4) इसके अलावा, अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 45 में यह प्रावधान है कि नियोक्ता ठेकेदार को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस (अनुबंध लागत का पांच प्रतिशत) और उपकरण अग्रिम (लागत का 90 प्रतिशत तक) देगा। इन अग्रिमों को ठेकेदार को देय भुगतान से आनुपातिक मात्रा में कटौती करके वापस लिया जाएगा।	नौ नमूना जिलों में से छह में, आठ सड़क परियोजनाओं के संबंध में (फरवरी 2009 से दिसंबर 2017 में) स्वीकृत ₹133.89 लाख में से, ₹46.52 लाख ⁴ का मोबिलाइजेशन/ मशीनरी अग्रिम, उन ठेकेदारों से (मार्च 2018 तक) वसूल नहीं किया गया था जिनको आवंटित की गई परियोजनाएं या जिनके अनुबंध जून 2014 से जून 2017 के दौरान समाप्त/ बंद किए गए थे।	ईई ने (मार्च से जून 2018) कहा कि डिवीजन ने ठेकेदारों के चालू बिलों से मोबिलाइजेशन/ मशीनरी अग्रिम में कटौती कर दी है और बकाया राशि पीआईयू के पास पड़े ठेकेदारों की सिक्योरिटी डिपॉजिट/ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से काट ली जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के बंद होने/ पूरा होने के पश्चात ठेकेदारों को अग्रिमों को पास रखने की अनुमति दी गई थी।
6.	बैंक गारंटियों का सत्यापन/ नवीनीकरण न किया जाना	पीएमजीएसवाई लेखा नियमावली के पैरा 13.2 में निर्धारित है कि बैंक गारंटी को स्वीकार करने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के सीधे बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी की प्रामाणिकता की पुष्टि करे। इसके अलावा, मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के खंड 32 में परिकल्पना की गई है कि स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को सफल बोलीदाता द्वारा नियोक्ता के नाम से किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बिना शर्त बैंक गारंटी या फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद के रूप में दिया जाएगा। बैंक गारंटी निर्माण अवधि तथा काम पूरा होने के बाद पांच साल के लिए वैध होनी चाहिए।	<ul style="list-style-type: none"> लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक-गारंटियों की पुष्टि किसी भी मामलों की जांच-परीक्षण में संलग्न नहीं पाई गई। 254 सड़क निर्माण कार्यों के अभिलेखों/ अलोटमेंट फाइलों कि संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि चार मामलों में निर्माण अवधि के दौरान ₹46.02 लाख की बैंक गारंटी की वैधता समाप्त हो चुकी थी या फिर उनको पुनः वैध नहीं किया गया था। 	

⁴ जम्मू: ₹2.12 लाख; रामबन: ₹9.63 लाख; गांदरबल: ₹11.26 लाख; अनंतनाग: ₹0.80 लाख; बारामूला: ₹2.17 लाख और कुपवाड़ा: ₹20.54 लाख

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	दिशा निदेशों के अनुसार आवश्यकता	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	विभाग का उत्तर
7.	अनुमोदित तकनीकी विशिष्टताओं से विचलन	तकनीकी संस्वीकृति के पश्चात, उसी रूप में कार्य हेतु निविदा जारी की जाएगी तथा एनआरआरडीए के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। (ओएम का पैरा 8.2)	नौ नमूना जिलों की 57 सड़क परियोजनाओं में, एनआरआरडीए का अनुमोदन प्राप्त किए बिना विभिन्न मर्दों का क्रियान्वयन हेतु ₹23.51 करोड़ खर्च किये गए जो अनुमोदित मात्रा से 11 से 8121 प्रतिशत ⁵ अधिक रहा।	ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि कार्यों का क्रियान्वयन साइट की स्थिति और अनुमोदित डीपीआर के अनुसार किया गया। जनता की मांगों को पूरा करने के लिए, परियोजना के कुछ घटकों को डीपीआर में दर्ज मात्रा की तुलना में अधिक मात्रा में क्रियान्वित करना पड़ा, परंतु आवंटित लागत के अंदर ही पूर्ण किया गया था। उत्तर को इस तथ्य के साथ देखा जाना चाहिए कि कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुमोदित मात्रा से अधिक मर्दों को क्रियान्वित करने से पहले एनआरआरडीए की अनुमति मांगा जाना आवश्यक है।
8.	साइनबोर्ड की स्थापना न करना	पीएमजीएसवाई के प्रतिकचिन्ह के साइनबोर्ड को कार्य आदेश की तारीख के 15 दिनों के भीतर लगाया जाना है। (ओएम का पैरा 8.14)	54 जांच-परीक्षण किए गए मामलों में ऐसे किसी भी साइनबोर्ड को नहीं लगाया गया।	
9.	परिसमापित क्षतियों (एलडी) का न लगाया जाना	ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर काम पूरा करने में विफल होने की स्थिति में प्रति सप्ताह प्रारंभिक अनुबंध मूल्य के एक प्रतिशत की दर से परिसमापित क्षतियों (एलडी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो कि प्रारंभिक अनुबंध मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत है। (ओएम का पैरा 9.10)	आठ नमूना जिलों ⁶ में 48 सड़क परियोजनाओं को ₹176.44 करोड़ की लागत पर प्रदान किया गया। ठेकेदारों ने दो महीने से छह साल और दो महीने के बीच की देरी से काम पूरा किया। इस देरी के लिए ठेकेदारों पर ₹17.64 करोड़ की राशि एलडी का आरोपण नहीं किया गया।	मुख्य अभियंता, पीएमजीएसवाई ने (अप्रैल 2019 में) कहा कि विभाग ने निर्धारित तिथि से परे काम पूरा करने में देरी के लिए ठेकेदारों पर एलडी आरोपण की प्रक्रिया शुरू की थी।

5 झाड़ंग और तकनीकी विनिर्देश के अनुसार खुदाई की गई भूमि की खाड़ियों को भरने के लिए 49 घन मीटर के काम के प्रति, 4028.22 घन मीटर की मात्रा रोन् से सुदगर तक सड़क निर्माण में पीआईयू उधमपुर द्वारा वास्तव में क्रियान्वित की गई थी

6 जम्मू: 2; उधमपुर: 3; रामबन: 3; गांदरबल: 6; अनंतनाग: 12; बारामूला: 4; कुपवाड़ा: 15 तथा लेह: 3

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यकता	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	विभाग का उत्तर
10.	प्रतिभूति जमा और निष्पादन प्रतिभूति को समय पूर्व जारी करना	मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) का खण्ड 43.2 में निर्माण कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने पर प्रतिभूति जमा ⁷ और निष्पादन प्रतिभूति ⁸ मुक्त करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित है जोकि इस शर्त के अधीन है कि अभियंता ने प्रमाणित किया है कि अभियंता द्वारा ठेकेदार को अधिसूचित किए गए सभी दोषों को ठेकेदार द्वारा पुनर्भुगतान के लिए निर्धारित अवधि से पहले ठीक कर दिया गया है।	नौ नमूना जिलों में से, आठ जिलों ⁹ में 43 सड़क परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, ₹6 करोड़ की प्रतिभूति जमा और ₹0.68 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति, एक महीने से चार साल की अवधि के लिए नियत तारीखों से पहले जारी की गई थी, इस प्रकार ठेकेदार को दोष देयता अवधि से पहले सिक्योरिटी को मुक्त करके अनुचित लाभ दिया गया।	ईई ने (मार्च जून 2018 में) कहा कि निर्देशों को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

(स्रोत: पीआईयू नमूनों के अभिलेख)

- 7 निर्माण कार्य के संतोषजनक रूप से पूरे होने पर प्रतिभूति जमा के रूप में रखी गई कुल राशि का आधा हिस्सा चुकाना होता है, 2 वर्ष के अंत में कुल राशि का एक चौथाई और शेष राशि तीसरे वर्ष के पूरा होने के बाद चुकानी होती है अथवा दोष देयता अवधि पूरी होने के पश्चात चरण-I के मामले में तीन साल और स्टेज-II के मामले में पांच साल (एसबीडी के खंड 43.4)
- 8 निष्पादन प्रतिभूति को दोष देयता अवधि के समापन के पश्चात मुक्त किया जाता है।
- 9 उधमपुर: 11; रामबन: 3; राजौरी: 2; गांदरबल: 6; अनंतनाग: 7; बारामूला: 4; कुपवाड़ा: 8 तथा लेह: 2

परिशिष्ट-2.2.7

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.9.4; पृष्ठ: 92)

नमूना जिलों में परीक्षण-जाँच कार्यों के एसक्यूएम के निरीक्षण को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	जिला	पीआईयू	सड़क परियोजनाओं की संख्या	एसक्यूएम द्वारा की गई जांच का विवरण				
				शून्य	एक	दो	तीन	तीन से अधिक
1.	जम्मू	जम्मू	07	-	02	-	02	03
2.	उधमपुर	उधमपुर	11	01	02	04	04	0
		रामनगर	14	-	03	03	04	04
3.	रामबन	रामबन	06	-	-	-	04	02
		बनिहाल	02	-	01	01	0	0
4.	राजौरी	राजौरी	11	01	01	01	05	03
		बुढ़ल	10	01	02	06	01	0
5.	गांदरबल	गांदरबल	11	-	-	02	05	04
6.	अनंतनाग	अनंतनाग	18	-	05	08	01	04
7.	बारामूला	बारामूला	01	-	-	-	0	01
		उरी	04	-	-	-	01	03
8.	कुपवाड़ा	कुपवाड़ा	19	-	03	06	03	07
		हंदवाड़ा	03	-	-	-	0	03
9.	लेह	लेह	03	-	01	-	01	01
		कुल	120	03	20	31	31	35

(स्रोत: नमूना पीआईयू के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.2.8

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.10; पृष्ठ: 96)

ओएमएमएस सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल

क्रम सं.	मॉड्यूल का नाम	मॉड्यूल का विवरण
I	मास्टर डाटा मॉड्यूल	जिलों, निर्वाचकों, खंडों, गाँव, प्रवास क्षेत्रों, पंचायतों, सड़कों तथा ठेकेदारों इत्यादि से संबन्धित मास्टर डाटा
II	कोर नेटवर्क (ग्रामीण सड़क योजना)	जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) सड़क डेटा (राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)/ राज्य राजमार्ग (एसएच)/ प्रमुख जिला सड़कें (एमडीआर)/ ग्रामीण सड़क/ लिंक मार्ग/ सीधे मार्गों का वर्गीकरण) से संबंधित डेटा
III	प्रस्ताव मॉड्यूल	कोर नेटवर्क से सड़क लिंक के चयन के आधार पर प्रस्ताव
IV	टेंडरिंग मॉड्यूल	टेंडरिंग डाटा, ठेकेदार को प्रदान किए गए का विवरण
V	क्रियान्वयन मॉड्यूल	कार्यों की प्रगति (वास्तविक/ वित्तीय)
VI	ऑनलाइन फंड प्रोसेसिंग	एसआरआरडीए से मंत्रालय को धन के लिए प्रसंस्करण अनुरोध को राज्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी आवश्यक और प्रासंगिक जानकारी जमा करके एमओआरडी से अनुरोध किया जाता है। मंत्रालय के परियोजना और वित्त विभागों से दोहरी मंजूरी के पश्चात, राज्य को स्वीकृत राशि और जारी की गई राशि को निर्दिष्ट करते हुए स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है।
VII	गुणवत्ता निगरानी मॉड्यूल	राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर्स (एनक्यूएम) द्वारा किए गए गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) निरीक्षण के संबंध में डेटा
VIII	प्राप्ति तथा भुगतान मॉड्यूल	प्रत्येक सड़क कार्य के प्रति वर्गीकृत व्यय से संबन्धित वित्तीय डाटा
IX	रख रखाव मॉड्यूल	पाँच वर्षों का वास्तविक तथा वित्तीय डाटा
X	सुरक्षा तथा प्रशासन मॉड्यूल	उपयोगकर्ताओं की रचना, भूमिकाओं के निर्माण, उपयोगकर्ताओं को भूमिकाओं के काम तथा भूमिका के मेन्यू की मैपिंग में मदद करता है
XI	ग्रामीण सड़कों के लिए दरों का विश्लेषण (एआरआरआर)	ग्रामीण सड़कों के लिए दरों का विश्लेषण (एआरआरआर) मॉड्यूल विभिन्न मदों के लिए शेड्यूल ऑफ रेट्स को बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है। शेड्यूल ऑफ रेट्स (एसओआर) भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा प्रकाशित "ग्रामीण सड़कों के लिए विनिर्देश" से प्राप्त कार्य की विभिन्न मदों के विश्लेषण पर आधारित थी।

क्रम सं.	मॉड्यूल का नाम	मॉड्यूल का विवरण
XII	प्राप्ति तथा भुगतान बैंक मॉड्यूल	बैंक मॉड्यूल का उपयोग बैंक कर्मियों द्वारा किया जाता है, जहां पर पीएमजीएसवाई कार्यों से संबंधित एसआरआरडीए का खाता हो। उस राज्य के डीपीआईयू द्वारा ठेकेदारों को जारी किए गए चेक या डीपीआईयू द्वारा उत्पन्न ई-भुगतान निर्देश यहाँ सूचीबद्ध हैं। जब बैंक किसी वाउचर से संबंधित चेक/ ई-भुगतान को मंजूरी देता है, तो बैंक प्राधिकरण लॉगिन करता है और उसका मिलान करता है और यह डीपीआईयू और एसआरआरडीए रिपोर्ट में प्रतिबिम्बित होता है।
XIII	डाटा अंतराल	प्रतिवेदन अनुभाग के तहत प्रस्तावों की प्रविष्टि में डेटा अंतराल को देखने का प्रावधान है।
XIV	उपयोगकर्ता मैनुअल का अद्यतन	उपयोगकर्ता पुस्तिका अद्यतित है और लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध है। उपयोगकर्ता मैनुअल में ओएमएमएस में नवीनतम संवर्द्धन संलग्नक के रूप में प्रदान किए गए हैं।

(स्रोत: ओएमएमएस मॉड्यूल)

परिशिष्ट-2.2.9

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.10; पृष्ठ: 97)

तुलन पत्रों में दर्शाये गए व्यय तथा अपलोड किए गए व्यय में अंतर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूर्ण नई सड़कों पर व्यय		प्रगतिशील नई सड़कों पर व्यय		पूर्ण नई सड़कों के उन्नयन पर व्यय		प्रगतिशील सड़कों के उन्नयन पर व्यय	
	सीए बी/एस	ओएमएमएस	सीए बी/एस	ओएमएमएस	सीए बी/एस	ओएमएमएस	सीए बी/एस	ओएमएमएस
2013-14	सीवाई- 998.07	सीवाई- 333.37	सीवाई- 1,124.87	सीवाई- 1,792.61	सीवाई- 93.24	सीवाई- 59.99	सीवाई- 237.64	सीवाई- 253.87
	पीवाई- 390.29	पीवाई- 215.37	पीवाई- 1,288.66	पीवाई- 1,445.59	पीवाई- 35.58	पीवाई- 46.75	पीवाई- 237.69	पीवाई- 218.93
2014-15	सीवाई- 1,245.02	सीवाई- 449.23	सीवाई- 1,294.77	सीवाई- 2,085.64	सीवाई- 163.84	सीवाई- 75.08	सीवाई- 191.01	सीवाई- 255.91
	पीवाई- 998.07	पीवाई- 333.37	पीवाई- 1,124.87	पीवाई- 1,792.61	पीवाई- 93.24	पीवाई- 59.99	पीवाई- 237.64	पीवाई- 253.87
2015-16	सीवाई- 1,517.82	सीवाई- 564.95	सीवाई- 1,213.08	सीवाई- 2,223.32	सीवाई- 233.60	सीवाई- 105.34	सीवाई- 173.23	सीवाई- 233.34
	पीवाई- 1,245.02	पीवाई- 449.23	पीवाई- 1,294.77	पीवाई- 2,085.64	पीवाई- 613.84	पीवाई- 75.08	पीवाई- 191.01	पीवाई- 255.91
2016-17	सीवाई- 1,895.40	सीवाई- 1,495.58	सीवाई- 1,229.00	सीवाई- 1,593.64	सीवाई- 290.95	सीवाई- 238.03	सीवाई- 145.36	सीवाई- 114.50
	पीवाई- 1,517.82	पीवाई- 564.95	पीवाई- 1,213.08	पीवाई- 2,223.32	पीवाई- 233.60	पीवाई- 105.34	पीवाई- 173.23	पीवाई- 233.34

(सीए बी/एस- सनदी लेखाकार तुलन पत्र, सीवाई- वर्तमान वर्ष, पीवाई- पिछला वर्ष)

(स्रोत: ओएमएमएस/ सनदी लेखाकार तुलन पत्र)

परिशिष्ट-3.1.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.1; पृष्ठ: 102)

एसकेयूएसटी-जम्मू के अंतर्गत अनुसंधान स्टेशनों/ केन्द्रों की सूची

(₹ लाख में)

क्रम सं	अनुसंधान स्टेशन का नाम	केंद्र में क्रियाशील परियोजना का नाम	फंडिंग एजेंसी/ योजना	प्रारम्भ होने की तिथि	पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि	बजट	नवम्बर 2018 तक व्यय
1.	एडवांस सेंटर फॉर रेनफेड एग्रीकल्चर (एसीआरए), ढींसर	नए जीन पूल का संश्लेषण के अनुगामी बीमारी के अंतःक्षेपण और द्वितीयक (फासीयोलस एक्वूटिफोलियस एल) जीन पूल से विकसित फासीयोलस वल्गेरिस में शुष्कता टोलरेंस।	विज्ञान तथा अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070	मार्च 2017	जारी	40.00	20.95
		शुष्क भूमि कृषि पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी)	शुष्क भूमि कृषि पर अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपीडी) शुष्क भूमि कृषि हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर, हैदराबाद	1972	जारी	122.14	84.16
		जलवायु परिवर्तन कृषि पर राष्ट्रीय पहल (एनआईसीआरए)	सीआरआईडीए, आईसीएआर, हैदराबाद	2011	जारी	आवश्यकता के अनुसार वार्षिक बदलाव	65.57
		जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी)	पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ), कृषि निदेशालय जम्मू (डीएजे) के माध्यम से भारत सरकार	फरवरी 2017	मार्च 2018 में बंद	10.00	10.00

क्रम सं.	अनुसंधान स्टेशन का नाम	केंद्र में क्रियाशील परियोजना का नाम	फंडिंग एजेंसी/ योजना	प्रारम्भ होने की तिथि	पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि	बजट	नवम्बर 2018 तक व्यय
2.	रेनफेड हॉर्टिकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, राया	वर्तमान में रेनफेड हॉर्टिकल्चरल रिसर्च सब-स्टेशन, राया में कोई बाह्य वित्त पोषित परियोजना नहीं है। हालांकि, केंद्र के पास सूखा सहिष्णु फलों पर व्यवस्थित अनुसंधान करने और वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त खेती करने, मिट्टी की नमी के संरक्षण आदि के लिए एक विशिष्ट अधिदेश है और यह कार्यशील है।					
3.	क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन, राजौरी	एग्रो-मेट्रोलाॅजिकल फील्ड यूनिट (एएमएफयू), ग्रामीण कृषि मौसम सेवा	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	2007	जारी	9.14	4.62
4.	रिजनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, भदरवाह	तापक्रमी फल की फसलों के लिए पारिस्थितिकी के आउटरीच पर नेटवर्किंग परियोजना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)	2009	जारी	वार्षिक लगभग 5.00 लाख	26.30
		जलवायु परिवर्तन कृषि (एनआईसीआरए) में राष्ट्रीय नवाचार - सामरिक अनुसंधान	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)	सितंबर 2017	जारी	1.60	1.33
5.	दलहन अनुसंधान उप-स्टेशन, सांबा	चिक्कपी अनुसंधान सांबा पर एआईसीआरपी	अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी)	1995	जारी	39.22	29.89
6.	मक्का अनुसंधान केंद्र, उधमपुर*	मक्का पर एआईसीआरपी	एआईसीआरपी	2006	मार्च 2018 में बंद	47.76	37.61

क्रम सं.	अनुसंधान स्टेशन का नाम	केंद्र में क्रियाशील परियोजना का नाम	फंडिंग एजेंसी/ योजना	प्रारम्भ होने की तिथि	पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि	बजट	नवम्बर 2018 तक व्यय
7.	एडवांस सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च, उधायवाला	बागवानी के लिए उत्कृष्ट केंद्र (फल)	बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच)	2015	जारी	78.00	78.00
		स्ट्रॉबेरी और कार्नेशन प्लांटलेट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए टिशू कल्चर लैब की स्थापना	एमआईडीएच	2015	जारी	121.70	120.17
		कृषि समुदाय के भोजन और आजीविका सुरक्षा के लिए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण को बढ़ावा देना	एमआईडीएच	जनवरी 2016	जारी	6.51	4.30
8.	मक्का प्रजनन अनुसंधान उप-स्टेशन, पुंछ	मक्का सुधार कार्यक्रम	(आईसीएआर)	2012	जारी	0.60	0.14

(*स्टेशन मार्च 2018 में बंद किया गया)

(स्रोत: अनुसंधान निदेशालय के अभिलेख)

परिशिष्ट-3.1.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.1; पृष्ठ: 102)

विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं (दीर्घावधि/ तदर्थ) का ब्योरा दर्शाता विवरण

क्रम सं.	फंडिंग एजेंसी का नाम	1 अप्रैल 2014 तक चालू परियोजनाएं	2014-18 के दौरान ली गई परियोजनाएं	कुल	2014-18 के दौरान पूर्ण की गई परियोजनाएं	छोड़ी गई परियोजनाएं	31 मार्च 2018 तक चालू परियोजनाएं	परियोजनाओं की प्रकृति		लघु अवधि परियोजनाएं	दीर्घ अवधि परियोजनाएं
								प्रयोगिक	मौलिक		
1.	अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना (आईसीएआर: 75 प्रतिशत; राज्य का हिस्सा: 25 प्रतिशत)	22	10	32	6	0	26	26	0	0	26
2.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (आईसीएआर: 100 प्रतिशत)	8	14	22	8	2	12	5	7	12	0
3.	विज्ञान तथा तकनीकी विभाग (आईसीएआर: 100 प्रतिशत)	10	18	28	10	1	17	10	7	17	0
4.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर: 100 प्रतिशत)	7	12	19	5	0	14	13	1	8	6
5.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आईसीएआर: 100 प्रतिशत)	1	17	18	6	0	12	12	0	12	0

क्रम सं.	फंडिंग एजेंसी का नाम	1 अप्रैल 2014 तक चालू परियोजनाएं	2014-18 के दौरान ली गई परियोजनाएं	कुल	2014-18 के दौरान पूर्ण की गई परियोजनाएं	छोड़ी गई परियोजनाएं	31 मार्च 2018 तक चालू परियोजनाएं	परियोजनाओं की प्रकृति		लघु अवधि परियोजनाएं	दीर्घ अवधि परियोजनाएं
								प्रयोगिक	मौलिक		
6.	कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (आईसीएआर: 100 प्रतिशत)	1	9	10	5	0	5	5	0	5	0
7.	बागवानी तकनीकी मिशन मोड / बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (आईसीएआर: 100 प्रतिशत)	5	12	17	15	0	2	2	0	2	0
8.	अन्य	8	14	22	11	1	10	7	3	10	0
	कुल	62	106	168	66	4	98¹⁰	80	18	66	32

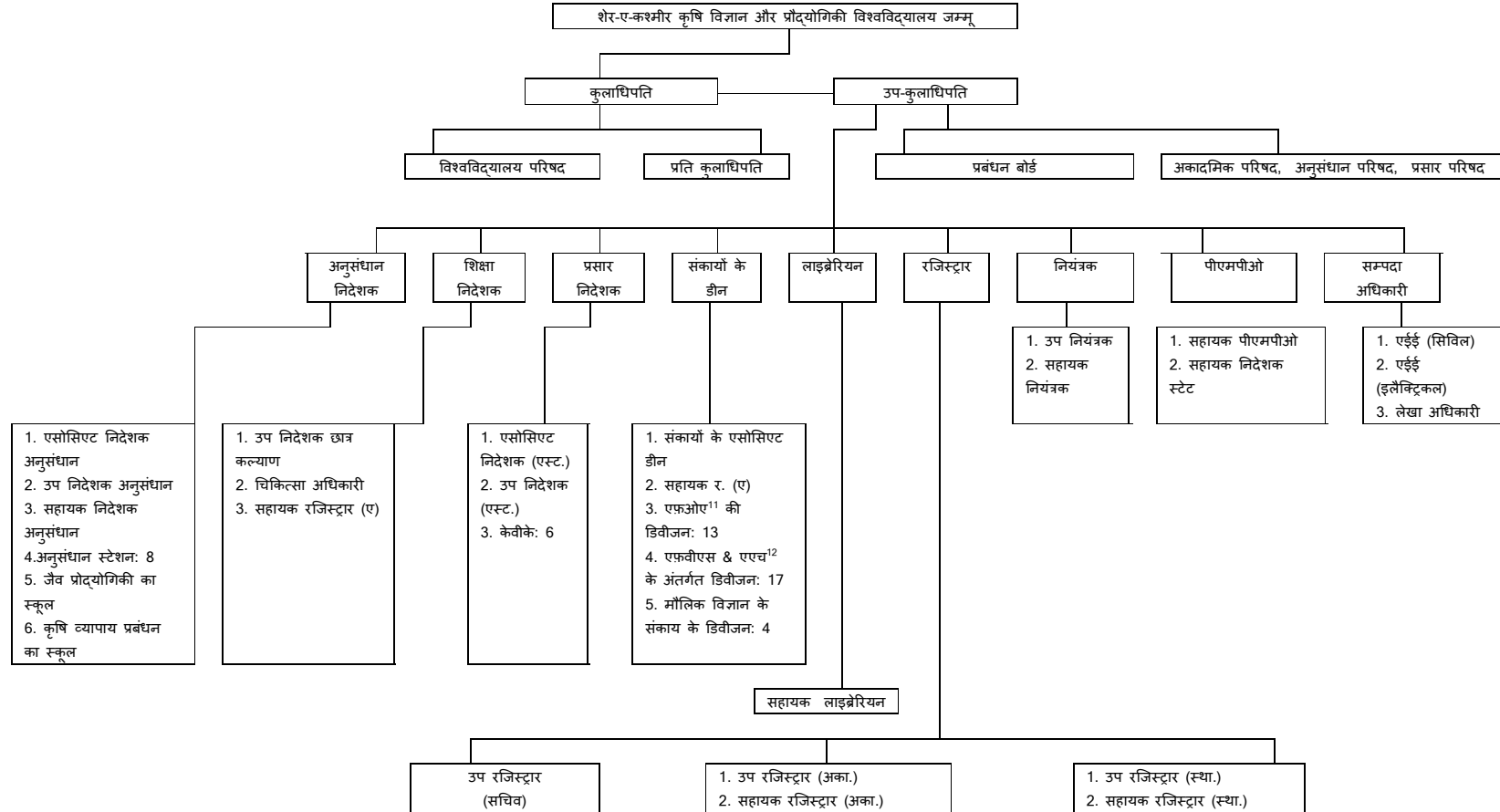
(स्रोत: अनुसंधान निदेशालय के अभिलेख)

¹⁰ कृषि: 81; पशु चिकित्सा: 13; बागवानी: 4

परिशिष्ट-3.1.3

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.1; पृष्ठ: 102)

एसकेयूएसटी जम्मू का संगठनात्मक ढांचा



(स्रोत: प्रभाव आकलन रिपोर्ट)

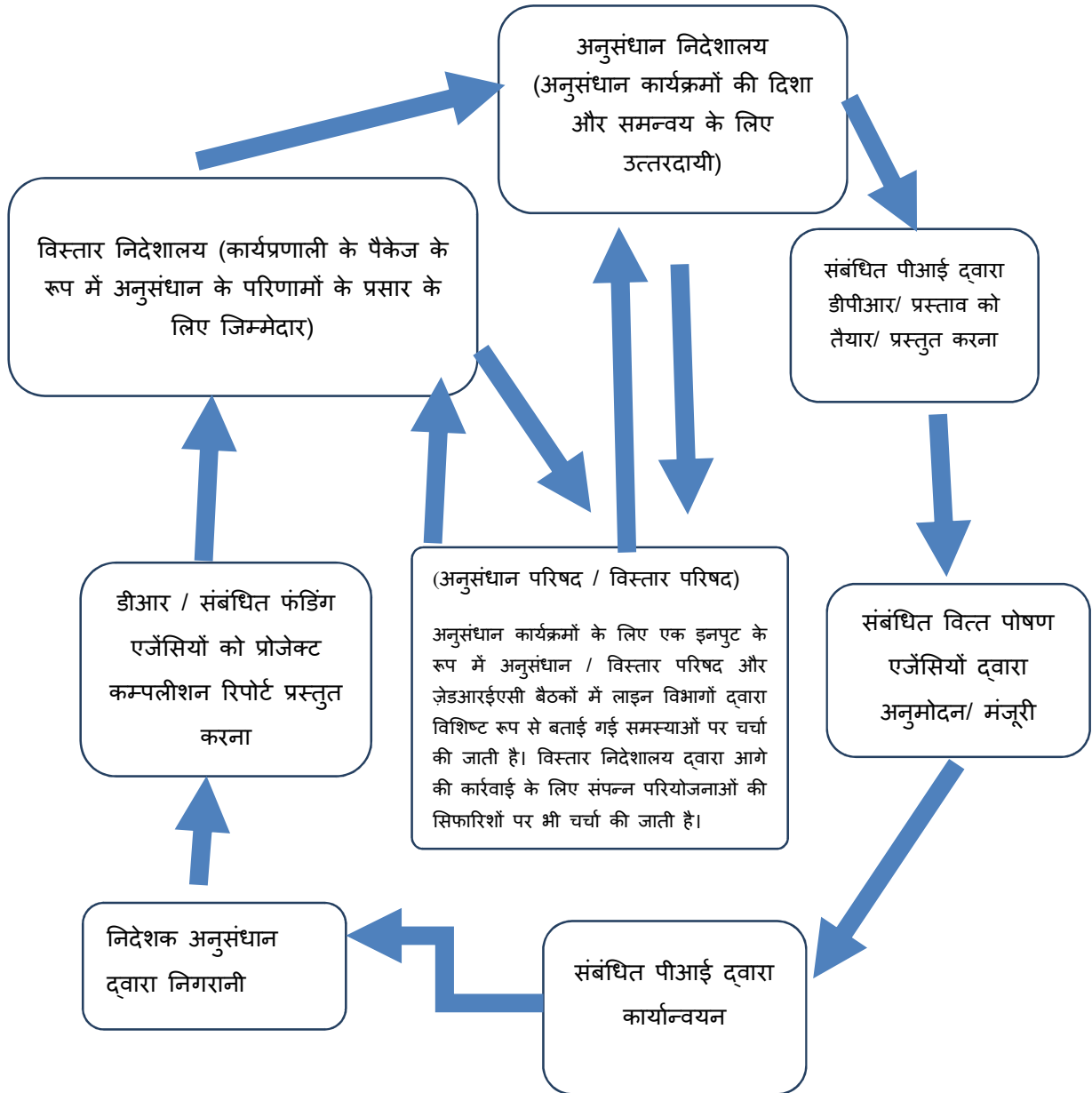
¹¹ एफओए: कृषि का संकाय

¹² एफवीएस तथा एएच: पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन का संकाय

परिशिष्ट-3.1.4

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.3; पृष्ठ: 105)

परियोजनाओं के चयन हेतु फ्लो चार्ट



- जेडआरईएसी: जोनल रिसर्च एंड एक्सटेंशन एडवाइजरी कमेटी
- पीआई: मुख्य अन्वेषक

(स्रोत: विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन)

परिशिष्ट-3.1.5

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.3; पृष्ठ: 105)

2011-12 और 2017-18 के बीच लाइन विभागों द्वारा उजागर किए मुद्दों का ब्यौरा दिखाता विवरण

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
रोग/ कीट प्रबंधन डिवीजन				
1.	गेहूं में पीले जंग के प्रकोप से रोकथाम में महत्वपूर्ण तकनीकी खोज	दिनांक 20-21 मई 2011, की 12वीं आरसीएम, दिनांक नवंबर 2015 की 15वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
2.	गेहूं की पाला प्रतिरोधी प्रजातियां	दिनांक नवंबर 2015 की 15वीं आरसीएम 2015 की कार्यवाही	लंबित	कृषि
3.	पीले जंग का शमन करने के लिए अधिक रसायन का समावेशन जो कि पौधा सुरक्षा रसायन की एकमात्र विशेषता है, पीले जंग (प्रोपिकोनाज़ोल) का प्रतिरोध बढ़ रहा है जैसा कि किसानों ने रिपोर्ट किया है	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	कृषि
4.	कांडी बेल्ट के सामान्य बुवाई वाले अनुपजाऊ क्षेत्रों के लिए पीले जंग प्रतिरोधी गेहूं की प्रजातियों का विकास तथा जीन परिनियोजन सम्मिलित द्वारा पूर्णतावादी प्रबंधन योजना का विकास, पैथोजेन प्रजातियों की पहचान इत्यादि	रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की बैठक तथा 17वीं अनुसंधान परिषद की दिनांक 20 मार्च 2018 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	कृषि
5.	पोड़ बोरर हमले तथा मुरझाने की प्रतिरोधात्मक क्षमता वाले चने की प्रजातियों का विकास	रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	कृषि

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
6.	किसानों की मदद तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु रोग प्रबंधन के लिए आकस्मिक योजना का विकास	दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
7.	उपयोग की गई दवाइयों के प्रति प्रतिरोधन का विकास जोकि पशुओं के प्रजनन को प्रभावित करता है तथा किसानों के घाटे का कारण होता है	17वीं आरसीएम दिनांक 20 मार्च 2018 को आयोजित की गई।	लंबित	पशु पालन
8.	क्षेत्रीय परिस्थितियों में चिचड़ी पर्याक्रमणों तथा दवाई प्रतिरोधन की समस्या पर ज़ोर देना। हिस्सेदारों के बीच आर्थिक घाटे को कम करने के लिए चिचड़ी पर्याक्रमणों के नियंत्रण हेतु नई दवाइयों के सुझाव	17वीं आरसीएम दिनांक 20 मार्च 2018 को आयोजित की गई।	लंबित	पशु पालन
9.	डेयरी पशुओं में "एक्टोपैरासाइट्स" का प्रबंधन	7वीं विस्तार शिक्षा परिषद की दिनांक 18 मई 2015 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	पशु पालन
10.	मादा बांझपान की समस्या से निपटना जिससे की ब्यांत अवधि कम की जा सके और डेयरी पशुपालन एक मुनाफे वाला उपक्रम बन सके।	दिनांक 21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम	लंबित	पशु पालन
11.	आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों की समस्या का निदान	दिनांक 21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम	लंबित	पशु पालन
12.	ब्रूसेल्लोस, लिस्टरिओसिस, ट्यूबरकुलोसिस, फूट रोट, एफएमडी इत्यादि रोगों का नियंत्रण तथा उन्मूलन	दिनांक 21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम	लंबित	पशु पालन
13.	एसीएचडी रामबन में जून-जुलाई के महीने में कीवी की नश्वरता को कम करने हेतु योजना।	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक	लंबित	बागवानी
14.	आलू क्षेत्रों में नीमटोड समस्या का प्रभावी नियंत्रण तथा जैव बासमती का सार्वजनिकीकरण	20 मार्च 2019 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	निदान किया गया	कृषि

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
15.	कठुआ जिले में किशतवाड़ और बानी में अखरोट घुन हेतु प्रबंधन अभ्यास	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
नई प्रजातियों के विकास/ प्रस्तुतीकरण डिवीजन				
1.	तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पंजाब के पैटर्न पर हयोला जैसे सफ़ेद सरसों तथा सरसों हाइब्रिड का प्रस्तुतीकरण	रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	कृषि
2.	विश्वविद्यालय द्वारा मक्का की उन्नत मिश्र किस्में/ हाइब्रिड का विकास जोकि निजी बहुराष्ट्रीय हाइब्रिड से सस्ती हों।	खरीफ 2015 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 11 मई 2015 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	कृषि
3.	बासमती की प्रकाशसुग्राही किस्म का विकास	दिनांक नवंबर 2015 की 15वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
4.	तिलहन तथा दालों की नई किस्मों का विकास	दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
5.	जम्मू डिवीजन के विभिन्न एगो-क्लाइमैटिक ज़ोन में कीवी का प्रस्तुतीकरण	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	बागवानी
6.	सफल पौधरोपण की सिफ़ारिश तथा लीची पौधरोपण की उत्तरजीविता	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
7.	हानिकारक बंदरों के ख़तरे से किसानों की रक्षा के लिए नकदी फसल के विकल्प के रूप में अदरक तथा हल्दी की ग्रीष्म बुवाई के स्थानीय चयन का विकास	रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की 15 दिसंबर 2016 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
8.	जम्मू डिवीजन के कांडी क्षेत्र में बेर की उन्नत किस्मों का प्रस्तुतीकरण	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
9.	मिड हिल्स में विभिन्न फल फसलों जैसे अनारदाना, फालसा इत्यादि का प्रस्तुतीकरण	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
10.	जम्मू रीजन के लिए उपयुक्त क्षेत्र विशेष मुख्य उन्नत फल फसल किस्मों की सूची प्रदान करना	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
बीज/ पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता				
1	विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड बीजों की किस्मों का उपयुक्त मात्रा में बहुलीकरण	20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
2	गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री की निश्चित उपलब्धता तथा पॉली बैग में उगाये गए बागवानी पौधे	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	बागवानी
3	पहाड़ी क्षेत्रों जैसे गिज़ा और के-448 के लिए पारंपरिक धान की किस्मों के बीज की उपलब्धता	खरीफ 2015 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 11 मई 2015 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	कृषि
4	ऊतक संवर्धित केसरी बीज कॉर्न का उत्पादन	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
5	बिक्री केंद्रों पर गुणवत्ता वाले फलों के पौधों का प्रावधान	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
6	उप उष्णकटिबंधी तथा समशीतोष्ण फलों जैसे आड़ू, बेर, सेब, आम तथा अमरूद की उच्च घनत्व तथा कम ठंडी किस्मों की उपलब्धता	रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की 15 दिसंबर 2016 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
7	जम्मू डिवीजन की समशीतोष्ण ज़ोन नर्सरियों के लिए सेब के क्लोनल रूटस्टोक की आपूर्ति तथा बहुलीकरण के लिए तकनीकी ज्ञान	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
तकनीकी/ आधारभूत संरचना/ संभार तंत्र सहयोग डिवीजन				
1	वातावरण प्रतिरोधकक्षमतापूर्ण कृषि विशेषतः यथावत आर्द्रता संरक्षण का विकास, परिरक्षित चारा निर्माण, चारे के स्रोतों तथा कृषि विभाग के साथ नजदीकी समन्वयन में एकीकृत कृषि प्रणाली का निर्माण	खरीफ 2015 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 11 मई 2015 की कार्यवाही	लंबित	कृषि
2	वातावरण प्रतिरोधकक्षमतापूर्ण किस्मों का विकास	20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
3	जम्मू प्रांत के अंतर्गत जुताई के लिए बासमती चावल की किस्मों की जैविक रूप द्वारा नाइट्रोजन की आवश्यकता का मानकीकरण और सिफारिश	20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
4	प्रविष्टियों की नकल किए जाने के बिना चावल के जीन पूल का संरक्षण	दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
5	बासमती क्लस्टर में जैविक चावल उत्पादन में सहयोग प्रदान करना तथा उपयुक्त कदमों को अपनाना	खरीफ 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 25 मई 2016 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	कृषि
6	आर.एस.पुरा बासमती की आनुवांशिक पहचान, शुद्धता (नमूने विभाग द्वारा प्रदान किए जाने थे) तथा रखरखाव की डीएनए जांच	खरीफ 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 25 मई 2016 की 12वीं आरसीएम, 20-21 मई 2011 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	कृषि

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
7	भूमि प्रजाति तथा स्थानीय जननद्रव जैसे कि भदरवाह रज्मश तथा आर.एस.पुरा बासमती सहित पौधों की किस्मों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।	20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
8	बासमती चावल में सुगंध की पहचान तथा सुगंध हेतु उत्तरदायी जीन की पहचान के लिए अनुसंधान कार्य	दिनांक 12 सितंबर 2013 की 14वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
9	भदरवाही रज्मश का डीएनए फिंगर प्रिंटर	दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
10	रज्मश का आणविक वर्णन	खरीफ 2015 के लिए ज़ेडआरईएसी दिनांक 11 मई 2015 की कार्यवाही	लंबित	कृषि
11	विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बताई गई जीआईएस आधारित मृदा उर्वरता मानचित्र की उपलब्धता विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की जानी है।	दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
12	शुष्क भूमि कृषि तथा आधुनिक जलसंभर के लिए परिवर्ती फसल प्रणाली का विकास	दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
13	पहाड़ी तथा चट्टान संबंधी कृषि मशीनों की डिज़ाइनिंग/ आयात नमूने	20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
14	उपयुक्त बुवाई कलेंडर तथा आकस्मिक फसल योजना को कारगर बनाने के प्रभावी यंत्र के रूप में एसकेयूएसटी-जे की कृषि मौसम विज्ञान शाखा द्वारा सभी जिलों के लिए खंड वार मौसम पूर्वानुमान	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	कृषि

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
15	मुर्गीपालन के मौसमी रोगों हेतु तकनीकी सहयोग तथा विश्वविद्यालय से उनके रोग निरोधी उपाय	8वीं शिक्षा विस्तार परिषद की 29 मार्च 2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	पशु पालन
16	एआई नेटवर्क पर डालने हेतु प्रजनन सांडो की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रजनन यंत्रों का प्रयोग	दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम	लंबित	पशु पालन
17	चारा संपन्नीकरण व पशु तथा मुर्गीपालन चारे में उपलब्ध स्थानीय चारा घटकों पर अनुसंधान ताकि किसानों को सस्ती दरों पर चारा तथा खनिज सम्पन्न चारा ब्लॉक उपलब्ध कराए जा सके।	दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम	लंबित	पशु पालन
18	जम्मू डिवीजन में अत्यंत-उच्च घनत्व के सेब के पौधरोपण की साध्यता और अनुकूलनशीलता तथा रूट स्टॉक सामग्री की सिफ़ारिश	9वीं शिक्षा विस्तार परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	बागवानी
19	मानकीकृत ऊतक समूह अभ्यास के साथ स्ट्रॉबेरी फल में गुणवत्ता सुधार	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	बागवानी
20	जम्मू डिवीजन के विशिष्ट रीज़नों के लिए ड्रैगन फ्रूट/ खजूर जैसी फल प्रजातियों की उन्नत किस्मों का विकास	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	बागवानी
21	अखरोट गिरी के मूल्य वर्धित उत्पाद	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	बागवानी
22	सूखा और अधिक वर्षा के लिए उचित आकस्मिक योजना	9वीं शिक्षा विस्तार परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	बागवानी

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्र

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
23	कांडी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त उर्वरता तकनीकों की सिफारिश की जानी चाहिए	20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	बागवानी
24	भेड़ में क्लेस्ट्रीडियल रोग के प्रबंधन हेतु क्लोस्ट्रीडियम टीके को तैयार करना	6वीं विस्तार परिषद की दिनांक 16 सितंबर 2013 बैठक एवं दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	भेड़ पालन
25	खनिजों की पर्याप्त मात्रा सहित पशुधन की पूर्ति हेतु पोषक तत्वों का खनिज मानचित्रण	6वीं विस्तार परिषद की दिनांक 16 सितंबर 2013 की बैठक एवं दिनांक मार्च 2018 की 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	भेड़ पालन
26	प्रत्येक जिले में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी और पशुधन का खनिज प्रोफाइल व पशुधन के लिए खनिजों की पूर्ति, जिनकी उस विशिष्ट क्षेत्र में कमी है।	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	भेड़ पालन
27	निदान और रोग प्रतिरोध के लिए मार्कर आधारित तकनीक का विकास	20 मार्च, 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम	लंबित	भेड़ पालन
28	स्थानीय नस्लों, लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे बकरवाल बकरी के आनुवंशिक लक्षण के वर्णन और संरक्षण, ईटीटी में सुधार, क्लोनिंग तकनीक आदि।	20 मार्च, 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	भेड़ पालन
29	शीघ्र पहचान और उचित उपचार के लिए रोगों की शीघ्र, सटीक और सस्ते निदान / रिपोर्टिंग के लिए नैदानिक सुविधाओं का अद्यतन	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की दिनांक 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	भेड़ पालन
30	जम्मू रीज़न में ऊन और मटन उत्पादन में सुधार हेतु प्रजनन उद्देश्य के लिए अच्छे भेड़ स्टॉक आयात करने का प्रयास	दिनांक 9 मार्च 2017 को अनुसंधान परिषद की 16वीं बैठक की कार्यवाही	लंबित	भेड़ पालन

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
31	भेड़ पालन विभाग और एसकेयूएसटी-जे द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भेड़ और बकरी की नियमित रखवाली, निगरानी और उनके रोगों का पता लगाने की आवश्यकता है।	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	भेड़ पालन
32	गेंदा फसल में मूल्यवर्धन	रबी 2016 के लिए जेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की कार्यवाही	लंबित	पुष्पकृषि
33	वाणिज्यिक बागवानी फसलों की खेती में सूक्ष्म सिंचाई तकनीक	रबी 2016 के लिए जेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की कार्यवाही	लंबित	पुष्पकृषि
34	गेंदे में मूल्यवर्धन की विधियाँ	दिनांक 29 मार्च, 2017 को 8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की कार्यवाही	लंबित	पुष्पकृषि
35	सूखे पौधे की अवधारणा का परिचय	8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की दिनांक 29 मार्च, 2017 की कार्यवाही	लंबित	पुष्पकृषि
36	फसलोत्तर तकनीक का परिचय	8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की दिनांक 29 मार्च, 2017 की कार्यवाही	लंबित	पुष्पकृषि
37	गेंदे की संरक्षित खेती का परिचय	8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की दिनांक 29 मार्च, 2017 की कार्यवाही	लंबित	पुष्पकृषि
38	मिल्की मशरूम, बटन मशरूम और ढींगरी मशरूम हेतु लाइन विभागों की स्पॉनिंग तकनीक के मानकीकरण के संबंध में प्रौद्योगिकी	खरीफ 2015 के लिए जेडआरईएसी की दिनांक 11 मई 2015 की कार्यवाही	निदान किया गया	कृषि
39	जिला सांबा के लिए 0.2 हेक्टेयर, 0.5 हेक्टेयर और 1.0 हेक्टेयर के लिए एकीकृत खेती मॉडल (सिंचित / वर्षा आधारित खेती के लिए)	रबी 2017 के लिए जेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	कृषि

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
40	जम्मू डिवीजन में ग्रीष्मकालीन सेब की खेती के लिए मूल्यांकन और सिफारिशें	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
41	उच्च घनत्व वाले आम के बागों की लागत की मितव्ययता का अनुमान और अनुशंसित किस्में	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
42	राजौरी जिले में 3-4 वर्षों के बाद खट्टे फलों के आकार में कमी की समस्या	रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की 15 दिसंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
43	जम्मू डिवीजन के मृदा उर्वरता नक्शे का मानकीकरण और नए फल की फसल के रोपण से संबंधित सिफारिशें	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
44	अनार/ पपीता/ केले की प्रजातियों की तैयारी के लिए आगामी टिशू कल्चर लैब बहुलीकरण का विकास	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
45	केला, पपीता और अनार के फल की फसलों के व्यापक बहुलीकरण के लिए उत्कृष्ट केंद्र में टिशू कल्चर लैब का विविधीकरण	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
46	जिला स्तर पर संरक्षित संरचना और नर्सरी प्रौद्योगिकी के संबंध में तकनीकी सहायता प्रदान करना	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
47	मिट्टी की उर्वरता उत्पादन और फल की फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र विशेष में जैविक खेती पद्धति का अभ्यास	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
48	फलों की फसलों में बागवानी के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
49	फल फसलों जैसे बेर, करौंदा, गलगल, जामुन, अनार, हरड़, फलसा, आदि के लिए जम्मू के कंडी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट शुष्क भूमि बागवानी का गठन	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
50	जैव नियंत्रण एजेंटों का विकास/ मानकीकरण और बागवानी फसलों के लिए आईएनएम/आईपीएम के लिए सिफारिश	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
51	प्रमुख फसलों दालों, तिलहन, सब्जियों और बागवानी, फूलों की खेती, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, मशरूम, कृषि, वर्मीकम्पोस्ट से संबंधित विभिन्न उद्यम/ अर्थव्यवस्था से 2022 तक कृषि समुदाय की आय को दुगुना करने हेतु ऐसे मॉडल अपनाने के लिए के लिए प्रेरित करने हेतु विभिन्न फसलों के लिए वित्तीय प्रतिलाभ की तैयारी	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
52	जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में फलों की फसलों के संबंध में अनुकूलन रणनीतियां और बेहतर किस्में	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
53	कंडी क्षेत्रों में विभिन्न सुगंधित फसलों की अर्थव्यवस्था	रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की 15 दिसंबर 2016 की कार्यवाही	निदान किया गया	पुष्पकृषि
54	वाणिज्यिक बागवानी फसलों की नई जारी किस्मों की सिफारिश यथा जम्मू रीज़न के विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में जेरबेरा, लिलियम और गेंदा	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की कार्यवाही	निदान किया गया	पुष्पकृषि

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
55	छोटे गेंदे वाले किसानों के लिए पॉली हाउस की सिफारिश	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की कार्यवाही	निदान किया गया	पुष्पकृषि
56	पॉली हाउस में स्वचालन/सापेक्ष आर्द्रता की सिफारिश	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की कार्यवाही	निदान किया गया	पुष्पकृषि
57	जरबेरा के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की सिफारिश	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की कार्यवाही	निदान किया गया	पुष्पकृषि
तकनीक का प्रदर्शन/अनुशांसा/संवर्धन/स्थानांतरण				
1	यूरिया मोलासेस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक्स (यूएमएमबी) के संबंध में राजौरी, डोडा, रियासी, कठुआ और जम्मू जिलों में डेयरी पशु के लिए क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण से समृद्ध तकनीक का प्रसार	8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 29 मार्च, 2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	पशु पालन
2	आधारभूत संरचनात्मक आंकड़ों के प्रसार के विषय में बताया गया कि किसानों के बीच बकरवाली बकरी की कीमती और अद्वितीय नस्ल के संबंध में आंकड़ें विश्वविद्यालय द्वारा एकत्रित किए जाने हैं।	20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	भेड़ पालन
3	कर्तित फूलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों और गेंदे की विभिन्न किस्मों की ग्रीष्मकालीन खेती को जम्मू प्रांत के तहत वाणिज्यिक खेती को अनुशांसित करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय को नियंत्रित परिस्थितियों में संरक्षित खेती के लिए पर्यावरण अनुकूल तकनीक प्रदान करनी चाहिए ताकि किसानों की आय में वृद्धि के लिए एकीकृत मॉडल का विकास हो सके।	20 मार्च, 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	पुष्पकृषि

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
4	विभिन्न फसलों के लिए क्षेत्र विशिष्ट सिफारिशों की उपलब्धता	8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 29 मार्च, 2017 की कार्यवाही	लंबित	पुष्पकृषि
5	जम्मू क्षेत्र के समशीतोष्ण क्षेत्रों में उच्च घनत्व वाली सेब के पैकेज की पद्धति का विकास	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
6	अखरोट/ पेकान के अलावा अखरोट की फसलों को बढ़ावा देना	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
7	जम्मू रीज़न में अप्रयुक्त पड़े भूमि के बड़े हिस्से के लिए उपयुक्त फलदार पौधों की किस्मों की सिफारिश	20 मार्च, 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
8	जम्मू रीज़न में दामस्क गुलाब खेती को बढ़ावा देना	रबी 2016 ज़ेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की कार्यवाही	निदान किया गया	पुष्पकृषि

(स्रोत: अनुसंधान परिषद और ज़ोनल अनुसंधान विस्तार और सलाहकार समिति की बैठकों का कार्यवृत्त)

मंच	कुल मामलें	लंबित मामलें	निदान किए गए मामलें
आरसीएम	30	28	2
ज़ेडआरईएसी	42	16	26
ईसी	25	17	8
कुल योग	97	61	36

परिशिष्ट-3.1.6

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.3; पृष्ठ: 105)

2012 में पहचाने गए अनुसंधान योग्य क्षेत्रों की उपेक्षा दर्शाता विवरण

क्र.सं.	पहचाने गए क्षेत्र	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	अभ्युक्तियाँ
1	जर्मप्लाज्म बैंक की स्थापना और आनुवंशिक रूप से संशोधित / ट्रांसजेनिक फसलों का विकास	इसकी पहचान से 5 वर्ष से अधिक अवधि समाप्त होने के बाद राज्य कृषि उत्पादन विभाग को ₹4 करोड़ की लागत से अनुमानित जीन बैंक की स्थापना की परियोजना का प्रस्ताव (मार्च 2018) प्रस्तुत किया गया था।	आरंभ किया जाना है।
2	जलवायु परिवर्तन अनुसंधान और सुदूर संवेदन इकाई की स्थापना	चट्टा में प्रस्तावित परियोजना आरंभ करने हेतु धन की प्रतीक्षा थी। हालांकि, निदेशक कृषि, जम्मू को प्रस्तुत (अप्रैल, 2013) ₹94.20 करोड़ (12वीं योजना) की लागत की डीपीआर पर आगे की कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।	आरंभ किया जाना है।
3	भ्रूण हस्तांतरण तकनीक के माध्यम से भैंस की स्थानीय नस्लों में सुधार	कार्यकलाप आरंभ न करने के लिए धन की प्राप्ति न होने को जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि, विश्वविद्यालय द्वारा इस तरह के किसी प्रस्ताव को प्रारम्भ नहीं किया गया था।	आरंभ किया जाना है।
4	बकरवाली बकरियों पर डेटाबेस की स्थापना	एक परियोजना में बकरवाली बकरियों पर काम शुरू किया गया (जून 2018)। हालांकि, बकरवाली बकरी पर डेटाबेस की स्थापना का प्राथमिक क्षेत्र के निरूपण पर नेटवर्किंग परियोजना में संरेखित नहीं था, जिसमें प्ररूपी लक्षण के वर्णन का अधिदेश था	डेटाबेस की स्थापना पर कार्य आरंभ नहीं किया गया
5	वर्तमान में इस्तेमाल किए गए कीटनाशकों के विषविज्ञान का अध्ययन	मई 2018 तक इस तरह की कोई परियोजना आरंभ नहीं की गई थी। बताया गया (जून 2018) कि परियोजना कि फंडिंग के लिए आईसीएआर को प्रस्तुत किया जाएगा।	आरंभ नहीं हुआ

क्र.सं.	पहचाने गए क्षेत्र	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	अभ्युक्तियाँ
6	रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और मांस और दूध के उत्पादन के लिए पशुओं की जीनोटाइपिंग	मई 2018 तक इस तरह की कोई परियोजना आरंभ नहीं की गई थी। परियोजना के लिए बताया गया (जून 2018) कि फंडिंग के लिए आईसीएआर को प्रस्तुत किया जाएगा।	आरंभ नहीं हुआ
7	जीआईएस और रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करके जिला स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सूचनाओं का संग्रह और डिजिटलीकरण	इस तरह की कोई परियोजना आरंभ नहीं की गई थी। बताया गया कि परियोजना को प्रस्तुत किया गया है तथा धन की प्राप्ति के पश्चात आरंभ किया जाएगा।	आरंभ किया जाना है।
8	कीटों और रोगों के पूर्वानुमान के लिए डेटाबेस का विकास	उत्तर यह दर्शाते हुए सत्य नहीं है कि धन की अनुपलब्धता के कारण अनुमानित कार्य पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि यह परियोजना केवल ₹17.92 लाख की योजनागत लागत के विपरीत ₹6 लाख के लिए स्वीकृत की गई थी, जिसमें ₹4 लाख उपकरणों की लागत की ओर तथा ₹2 लाख आवर्ती आकस्मिकताओं के लिए तथा परियोजना को उपलब्ध अनुदान की सीमा के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए था। तथ्य यह भी है कि संकलित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बागवानी फसलों की उपस्थिति के बारे में आकड़ों को बागवानी निदेशालय के साथ साझा नहीं किया गया था।	परियोजना के मात्रात्मक उत्पादों जिसमें रोगजनकों की उत्तरजीविता का अध्ययन सम्मिलित है जो अगली फसल में इनोकुलम के प्राथमिक स्रोत, विभिन्न अंतराल पर रोगों के मूल्यांकन, रोग प्रगति वक्र के रूप में कार्य करता है और क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न तारीखों पर फसल के रोग और मौसम की स्थिति में बदलाव के आधार पर रोगों की उपस्थिति और गंभीरता के समय की भविष्यवाणी हेतु मौसम के मापदण्डों के अभिलेखों को प्राप्त नहीं किया गया था

क्र.सं.	पहचाने गए क्षेत्र	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	अभ्युक्तियाँ
9	कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर बारिश की कमी के प्रभाव का अध्ययन	राज्य के कृषि विभाग से फंडिंग के लिए 2014-15 में ₹42 लाख की लागत पर परियोजना को लिया गया था। हालाँकि, इस परियोजना के अंतर्गत केवल ₹5 लाख की धनराशि जारी की गई है और इसके बाद परियोजना को छोड़ दिया गया है।	अध्ययन को संचालित किया गया है और अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।
10	पशु रोग की अनुश्रवण और निगरानी (एडीएमएस) की स्थापना	हालांकि एडीएमएस लैब को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ स्थापित किया गया था, जो समय पर धनराशि जारी न होने से पूरी तरह कार्यात्मक नहीं हो सकी थी।	उत्पादों को प्राप्त नहीं किया गया।
11	महत्वपूर्ण फसलों के विकसित जीनोटाइप का विकास करने के लिए पारंपरिक प्रजनन प्रयासों में तेजी लाने हेतु आणविक प्रजनन (मार्कर सहायता प्राप्त चयन)	आणविक मार्करों पर परियोजनाओं के संचालन के विषय में बताया गया था कि इन परियोजनाओं के निष्कर्षों को अभी तक पीआई द्वारा संप्रेषित नहीं किया गया था। हालाँकि, 2006 तथा 2017 के बीच ₹62.03 लाख की लागत से संचालित दो परियोजनाओं के माध्यम से चावल/ बीन्स की नई खेती के विकास का उद्देश्य (जून 2018 तक) हासिल नहीं किया गया था।	संचालन में, परिणाम जांच के अधीन थे।
12	खाद्य और औषधीय मशरूम की उच्च उपज वाली नस्लों का चयन और परिचय	मशरूम पर दीर्घकालिक (एआईसीआरपी)/ लघु अवधि की परियोजनाएं चालू थीं। हालांकि, खाद्य और औषधीय मशरूम पर विशिष्ट सिफारिशें उपलब्ध नहीं थीं। अध्ययनों के परिणामों का सत्यापन किया जाना था (मई 2018)।	हालांकि, संचालन में परिणाम अपडेशन के तहत थे।

क्र.सं.	पहचाने गए क्षेत्र	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	अभ्युक्तियाँ
13.	चावल, गेहूं, मक्का और सामान्य फलियों में जैविक और अजैविक तनाव के लिए विभिन्न आणविक दृष्टिकोणों के माध्यम से जीन की खोज	जीन खोज पर परियोजना का संचालित होना बताया गया था। हालाँकि 2015 और 2016 में संपन्न हुई सामान्य बीन पर इस तरह की दो परियोजनाएँ किसी तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुँची थीं। इन परियोजनाओं के माध्यम से खोजे गए नवीन जीन का नई किस्मों की निर्गमन के लिए आगे उपयोग नहीं किया गया है।	निर्णयात्मक
14.	जीआईएस के माध्यम से कृषि योग्य भूमि और मिट्टी की उर्वरता मानचित्रण के लक्षण के वर्णन द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार	जीआईएस के माध्यम से मिट्टी के मानचित्रण पर विभिन्न परियोजनाओं के विषय में मृदा विज्ञान डिविजन में संचालित होना बताया गया था। हालाँकि, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) परियोजना को मृदा की उर्वरता के मूल्यांकन पर वित्त पोषित किया गया है और 2014-15 के दौरान जम्मू क्षेत्र के विभिन्न जिलों में डिजिटल मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार करने के उद्देश्य से जीआईएस का उपयोग करते हुए पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए इसकी स्थानिक विविधता अधूरी रह गई जैसा कि अप्रैल 2019 तक केवल दो जिले जिनमें जम्मू और कठुआ को कवर किया गया।	मिट्टी उर्वरता पर केवल आंशिक परिणाम उपलब्ध

(स्रोत: विश्वविद्यालय परिषद की बैठक का कार्यवृत्त)

परिशिष्ट-3.1.7

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.4.2; पृष्ठ: 109)

एसकेयूएसटी जम्मू में मांग के प्रति बीज उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़ें क्विंटल में)

वर्ष	मौलिक/बुनियादी फसल	इंडेंट	चट्टा में बीज उत्पादन	चाकरोई में उत्पादित बीज	कुल उत्पादन	कमी
2014-15	धान	800.00	98.29	174.86	273.15	526.85
	गेहूं	87,350.00	833.29	642.00	1,475.29	85,874.71
	योग	88,150.00	931.58	816.86	1,748.44	86,401.56
2015-16	धान	11,845.00	178.00	162.00	340.00	11,505.00
	गेहूं	90,000.00	51.56	133.53	185.09	89,814.91
	योग	1,01,845.00	229.56	295.53	525.09	1,01,319.91
2016-17	धान	13,150.00	336.75	243.00	579.75	12,570.25
	गेहूं	49,500.00	663.16	307.00	970.16	48,529.84
	योग	62,650.00	999.91	550.00	1,549.91	61,100.09
2017-18	धान	460.00	259.00	250.00	509.00	(-) 49.00
	गेहूं	9,102.00	539.25	255.00	794.25	8,307.75
	योग	9,562.00	798.25	505.00	1,303.25	8,258.75
कुल योग		2,62,207.00	2,959.30	2,167.39	5,126.69	2,57,080.31

(स्रोत: मेगा बीजों के अभिलेख)

परिशिष्ट-3.1.8

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.4.4; पृष्ठ: 111)

बंद की गई/ अवरुद्ध परियोजनाओं का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	तदर्थ परियोजना का नाम (परियोजना अवधि तीन वर्ष)	लागत	उद्देश्य/उत्पाद	अभ्युक्तियाँ	किया गया व्यय	विभाग का उत्तर
1.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), ब्रेसिका जंकिया के लिए एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिम्स (एसएनपी) का विकास आरंभ करने की तिथि: जुलाई 2013 समापन तिथि: 2017	58.43	एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलिमोर्फिम्स (एसएनपी) जीनोटाइपिंग के लिए उच्च-थ्रूपुट मल्टीप्लेक्स सारणी का संश्लेषण	उपकरणों की खरीद और आवश्यक सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए समय पर कार्रवाई की नहीं करने के परिणामस्वरूप क्रियान्वयन में देरी हुई। 2016-17 में परियोजना के लिए अतिरिक्त समय और अव्ययित अनुदान के उपयोग के लिए अनुरोध, फंडिंग एजेंसी द्वारा सहमति नहीं ली गई थी और ₹22.24 लाख की अव्ययित राशि फंडिंग एजेंसी को वापस की जानी थी (अक्टूबर 2017)	26.76	पीआई ने कहा (मार्च 2018) कि खरीद शुरू करने में केंद्रीय खरीद समिति द्वारा देरी के कारण परियोजना को नुकसान हुआ जो उसके नियंत्रण से बाहर था।
2.	ब्रेसिका जंकिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के वांछनीय किस्मों में इरुसिक एसिड प्रोफाइलिंग और निम्न इरुसिक एसिड का अंतर्गमन। आरंभ करने की तिथि: अगस्त 2014 समापन तिथि: अगस्त 2017	35.93	गुणवत्ता वाले तेल की मांग को पूरा करने के लिए कम इरुसिक एसिड अवयव के साथ ब्रेसिका जनेशिया के जर्मप्लाज्म का विकास।	यूसी को अपलोड करने में तकनीकी विफलता और परियोजना के तीसरे वर्ष के लिए अनुदान जारी न करने के परिणामस्वरूप, तीसरे वर्ष परियोजना की गतिविधियों को हानि पहुंची। परियोजना के समय को बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था।	22.90	पीआई ने कहा (मार्च 2018) कि डीबीटी के टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार, तीसरे वर्ष के तकनीकी कार्यक्रम को बिना किसी वित्तीय सहायता के चलाने और परिणामों को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए काम जारी रखने की सलाह दी गई थी। हालांकि, डीबीटी के प्रमुख ने कहा (जून 2018) कि परियोजना को बंद करने से आगे की प्रजनन प्रगति अवरुद्ध हो गई है और आज तक प्रजनन कार्यक्रम में आगे की सिफारिश के लिए संयुग्मजी लाइनों को विकसित नहीं किया जा सका है।
3.	एंज़ोजेनिसिस ने जोती हुई बैंगन (डीबीटी) की फसल में फल और अंकुर	26.40	भ्रूण के बचाव और स्थानीय परिस्थितियों के लिए प्रोटोकॉल का	निवर्तमान पीआई के पक्ष में एनओसी जारी करने से पहले सह-पीआई/ मॉटर को परियोजना का हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं किया	17.50	इंगित किए जाने पर, यह कहा गया (फरवरी 2018) कि परियोजना को स्थानांतरित करने का कोई

क्रम सं	तदर्थ परियोजना का नाम (परियोजना अवधि तीन वर्ष)	लागत	उद्देश्य/उत्पाद	अभ्युक्तियाँ	किया गया व्यय	विभाग का उत्तर
	प्रतिरोधी जीन की मध्यस्थता की। आरंभ करने की तिथि: फरवरी 2012 समापन तिथि: अगस्त 2014		मानकीकरण किया जाए तथा फलों के विकास और एंथर/माइक्रोस्पोर कल्चर के लिए और बैंगन की व्यापक हाइब्रिड के पराग रोपण प्रतिरोधी हेल्प्लोयड्स/ डबल हैप्लोयड्स का विकास।	गया था, हालांकि डीबीटी द्वारा परियोजना के हस्तांतरण के प्रावधान की सूचना निवर्तमान पीआई को एक विज्ञप्ति में सूचित की गई थी।		प्रावधान नहीं था। उत्तर का समर्थन करने वाला दस्तावेज़ केवल तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए पीआई की अनुपस्थिति के मामले में स्थानांतरण को प्रतिबंधित करता है, जो इस मामले में प्रासंगिक नहीं है। उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखकर भी देखा जाना चाहिए कि परियोजना के हस्तांतरण के लिए प्रावधान डीबीटी द्वारा निवर्तमान पीआई को एक विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया गया था, जिसके आधार पर पीआई द्वारा एनओसी लागू किया गया था।
4.	भारत के मृदा कार्बन पूल का स्थानिक मूल्यांकन आरंभ करने की तिथि: 2008 समापन तिथि: 2012 (2012 के बाद की कोई जानकारी नहीं)	2.80	आगे के विश्लेषण के लिए मिट्टी के नमूनों के संग्रहण द्वारा कार्बन चक्र के घटकों का अनुमान	परियोजना में पीआई का लगातार परिवर्तन हुआ जिसके परिणामस्वरूप इसका कुप्रबंधन हुआ। जुलाई 2010 तक, विभिन्न भूमि उपयोग पैटर्न के अंतर्गत केवल 29 मिट्टी प्रोफाइल नमूने एकत्र किए गए थे। तीसरे पीआई ने (मई 2012) विभिन्न स्थानों पर मिट्टी के नमूने के लिए अपना नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई और परियोजना को अनिवार्य उद्देश्यों को पूरा किए बिना बर्खास्त किया गया।	0.40	मिट्टी के नमूनों को एकत्र करने और संबंधित क्वार्टरों में भेजने के लिए कहा गया था। हालांकि, परियोजना से संबंधित सभी रिकॉर्ड के संबंध में बताया गया कि वे बाढ़ में नष्ट हो गए थे। हालांकि, तथ्य यह है कि राष्ट्रीय कार्बन बजट के संकलन के लिए सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों को कवर करने के लिए मिट्टी वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक समूह की भागीदारी के अभाव में और पीआई के लगातार परिवर्तन के कारण, परियोजना आगे बढ़ने में विफल रही।

क्रम सं	तदर्थ परियोजना का नाम (परियोजना अवधि तीन वर्ष)	लागत	उद्देश्य/उत्पाद	अभ्युक्तियाँ	किया गया व्यय	विभाग का उत्तर
5.	<p>फलों की फसलों के लिए उच्च नस्ल रोपण सामग्री के लिए मदर प्लांट नर्सरी की स्थापना (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड) आरंभ करने की तिथि: सितंबर 2012</p> <p>जून 2014 के बाद की कोई परियोजना गतिविधियां नहीं</p>	43.00	साइट्स और अमरूद की उच्च उपज वाली किस्मों का बहुलीकरण किया जाना और बगीचेवालों को आपूर्ति किया जाना।	<p>2012-13 के दौरान परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जा सका और अंत में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच) के तहत विश्वविद्यालय द्वारा एक अन्य परियोजना "बागवानी फल के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना" के तहत वृक्षारोपण हेतु बीच में छोड़ दिया गया, जिसकी अनुमानित लागत ₹784 लाख थी (फरवरी 2016)। परियोजना क्षेत्रों के अतिव्यापी होने के कारण, परियोजना के तहत पहले से ही निर्मित खट्टे फलों के मदर ब्लॉक को उखाड़ फेंकना पड़ा, जिसके लिए फंडिंग एजेंसी से रिकॉर्ड पर कोई औपचारिक मंजूरी नहीं ली गई थी। इसके अलावा, पीआई द्वारा मांगी गई परियोजना (जनवरी 2017) के लिए अतिरिक्त समय/ स्थानांतरण के लिए किसी भी अनुमोदन के अभाव में परियोजना की गतिविधियाँ अवरूद्ध थीं। इस प्रकार, साइट्स और अमरूद की एचवाईवी के बहुलीकरण करने और बागवानों को इसकी आपूर्ति की जाए, ताकि इससे किसान प्रामाणिक रोपण सामग्री प्राप्त कर सकें, जो उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और आय बढ़ा सकें, ऐसी योजना के वास्तविक उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सके।</p>	21.73	<p>जवाब में, यह कहा गया (अप्रैल 2018) कि पीआई द्वारा अनुरोध की गई नर्सरी (जनवरी 2017) की परियोजना के लिए अतिरिक्त समय और स्थानांतरण हेतु अनुमति आज तक प्रतीक्षित थी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना बंद हो गई। हालाँकि, तथ्य यह रहा कि परियोजना स्थलों का अतिव्यापीकरण गलत नियोजन का संकेत था।</p>
	कुल	166.56			89.29	

(स्रोत: अनुसंधान निदेशालय के अभिलेख)

परिशिष्ट-3.1.9

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.4.5; पृष्ठ: 112)

कोर ब्रीडिंग कार्यक्रम में अनुसंधान परिणामों का गैर-एकीकरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	व्यय	पूर्ण होने की तारीख	उद्देश्य/ अनुमानित परिणाम	उपलब्धि	अभ्युक्तियाँ
1.	भागीदारी के दृष्टिकोण से माध्यम आणविक मार्करों और इन-सीटू संरक्षण का उपयोग करते हुए बासमती चावल की आनुवंशिक विविधता का आकलन	19.13	19.13	2014	निर्यात गुणवत्ता की किस्मों के विकास के लिए बासमती के उन्नत जीनोटाइप का विकास	नई दिल्ली के प्लांट जेनेटिक रिसर्च के नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट में जमा विविध स्थानीय भू-भाग किस्म के बासमती	इन जीनोटाइप को परियोजना में परिकल्पित निर्यात के उद्देश्यों के लिए वांछित किस्मों के विकास के लिए आगे के क्रॉसिंग कार्यक्रमों में उपयोग नहीं किया गया था।
2.	सामान्य फलियों के बीच आनुवंशिक विविधता का निर्धारण और वॉटर स्ट्रेस टोलरेंस का मूल्यांकन (डीएसटी)	22.40	21.50	जून 2015	जल तनाव प्रतिरोध की सामर्थ्य रखने वाले वांछनीय किस्म के बीन जीनोटाइप की पहचान/ मूल्यांकन	<ul style="list-style-type: none"> उच्च लौह जस्ता प्रोटीन सामग्री वाले जीनोटाइप की पहचान की गई है वर्षा आधारित परिस्थितियों में उच्च उपज वाले जीनोटाइप की पहचान की गई है 	आणविक हस्तक्षेपों का उपयोग करके पहचाने गए 96 विविध जीनोटाइपों के सेट का उपयोग आगे के प्रजनन कार्यक्रमों के लिए नहीं किया गया है ताकि जल तनाव प्रतिरोधी किस्मों के विकास के अपेक्षित दीर्घकालिक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

3.	सामान्य बीन (डीओसी) में जिंक, आयरन और प्रोटीन सामग्री के लिए जीन की पहचान के लिए न्यूट्री-जीनोमिक्स और ट्रांसक्रिप्टोमिक्स	21.50	19.50	जुलाई 2016	जस्ता, लोहा और प्रोटीन सामग्री के लिए विभेदित रूप से व्यक्त जीन के सेट की पहचान	सीड जिंक, सीड आयरन, प्रोटीन, शर्करा/ स्टार्च सामग्री/ फेनोल, उपज का योगदान लक्षण और एन्थ्रेक्नोज प्रतिरोध के लिए जीनों की पहचान	एसएसआर मार्कर जीनोटाइपिंग/ वांछनीय लक्षणों के लिए सटीक हाई-थ्रूपुट मार्कर जीनोटाइपिंग का उपयोग करके पहचानी गई 96 लाइनों के मुख्य सेट का नई बीन किस्मों की उन्नत गुणवत्ता, उपज और रोग प्रतिरोध के साथ विकास हेतु उन्नत बीन आणविक प्रजनन कार्यक्रमों का उपयोग आगे नहीं किया गया था।
4.	जम्मू रीजन में चावल में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल (सीएमएस) प्रणाली का उपयोग करते हुए बासमती हाइब्रिड का विकास	1.91	1.91	2006	वांछित लक्षणों को शामिल करके बासमती हाइब्रिड का विकास।	प्रभावी पुनर्स्थापकों और अनुरक्षकों की पहचान के लिए 3 बासमती सीएमएस लाइनों (पूसा 3ए, 5ए और 6ए) का मूल्यांकन	पहचान की गई लाइनों को उनके पुनर्स्थापकों के साथ परिकल्पित रूप में बासमती हाइब्रिड को जारी करने के लिए मुख्य प्रजनन कार्यक्रम में एकीकृत नहीं किया गया था, हालांकि बीज उत्पादन को मानकीकृत किया गया था।
	कुल	64.94	62.04				

(स्रोत: अनुसंधान निदेशालय के अभिलेख)

परिशिष्ट-3.1.10

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.5.1; पृष्ठ: 114)

प्रयोगशाला से खेतों तक तकनीक हस्तांतरण संबंधी परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं.	परियोजना का शीर्षक	बजट (₹ लाख में)	फंडिंग एजेंसी का नाम	आरंभ करने का वर्ष	पूर्ण होने का वर्ष
1	खानाबदोशों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए भेड़, बकरियों और खानाबदोश महिलाओं के सामान्य परजीवी जूनोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए हस्तक्षेपी रणनीतियाँ	2.58	नाबार्ड	2013	2017
2	विसटर चूहों में प्रजनन सूचकांकों के विशेष संदर्भ के साथ धातुक्षय प्रेरित विकासात्मक विषाक्तता को नियंत्रित करने वाला तंत्र	16.79	राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, जम्मू और कश्मीर सरकार	2011	2014
3	जम्मू और कश्मीर में पर्यटन और तीर्थयात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाले घोड़ों के महत्वपूर्ण उभरते जूनोटिक रोग	14.64	आईसीएमआर, नयी दिल्ली	2011	2014
4	एनिमल डिजिज़ मॉनिटरिंग एवं सर्विलांस (एडीएमएएस) लैब्स।	31.00	राज्य सरकार	2012	2015
5	ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए डेयरी पशुओं में प्रजनन और प्रबंधन रणनीति	15.80	डीएसटी	2010	2014
6	जम्मू जिले में बोवाइन क्रिप्टोस्पोरिडिओसिस और इसकी जूनोटिक सामर्थ्य	27.00	डीबीटी	2011	2015
7	जम्मू और कश्मीर में पशुधन में विभिन्न बीमारियों के उपचार में उपयुक्त कार्यप्रणाली के पैकेज के दस्तावेज़ों का सत्यापन और विस्तार	8.44	डीएसटी	2011	2014
	योग	116.25			

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट-3.4.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.4; पृष्ठ: 125)

पूर्व-संशोधित दरों पर खाद्यान्नों की बिक्री दर्शाता विवरण

क्रम सं	सहायक निदेशक का नाम (एफसीएस एवं सीए)	महीने	वस्तु	श्रेणी	बेची गई मात्रा (क्विंटल में)	प्रभारित दरें (₹ प्रति क्विंटल)	प्रेषित राशि (₹ लाख में)	प्रभारित की जाने वाली दरें (₹ प्रति क्विंटल)	प्रेषित की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	अल्प प्रेषण (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6x7)	(9)	(10=6x9)	(11=10-8)
कश्मीर डिवीजन										
1.	बारामूला	अक्टूबर 2016	चावल	एनपीएचएच	17,789.79	1,000	177.90	1,500	266.85	88.95
2.	पुलवामा	अक्टूबर तथा नवंबर 2016	चावल	एनपीएचएच	21,081.33	1,000	210.81	1,500	316.22	105.41
3.	शोपियाँ	अक्टूबर तथा नवंबर 2016	चावल	एनपीएचएच	9,793.21	1,000	97.93	1,500	146.90	48.97
4.	कुपवाड़ा	अक्टूबर 2016	चावल	एनपीएचएच	11,350.36	1,000	113.50	1,500	170.26	56.76
5.	गांदरबल	अक्टूबर तथा नवंबर 2016	चावल	एनपीएचएच	9,719.37	1,000	97.19	1,500	145.79	48.60
6.	बांटीपोरा	अक्टूबर तथा नवंबर 2016	चावल	एनपीएचएच	9,904.11	1,000	99.04	1,500	148.56	49.52
7.	अनंतनाग	अक्टूबर 2016	चावल	एनपीएचएच	13,581.16	1,000	135.81	1,500	203.72	67.91
8.	बडगाम	अक्टूबर 2016	चावल	एनपीएचएच	11,438.89	1,000	114.39	1,500	171.58	57.19

क्रम सं.	सहायक निदेशक का नाम (एफसीएस एवं सीए)	महीने	वस्तु	श्रेणी	बेची गई मात्रा (क्विंटल में)	प्रभारित दरें (₹ प्रति क्विंटल)	प्रेषित राशि (₹ लाख में)	प्रभारित की जाने वाली दरें (₹ प्रति क्विंटल)	प्रेषित की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	अल्प प्रेषण (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6x7)	(9)	(10=6x9)	(11=10-8)
9.	कुलगाम	अक्टूबर 2016	चावल	एनपीएचएच	7,698.10	1,000	76.98	1,500	115.47	38.49
जम्मू डिवीजन										
10.	रेयासी	अक्टूबर 2016	गेहूं	एनपीएचएच	616.66	725	4.47	1,200	7.40	2.93
			चावल		1,165.47	1,000	11.65	1,500	17.48	5.83
			आटा		1,364.30	800	10.91	1,300	17.74	6.83
11.	कठुआ	अक्टूबर 2016	गेहूं	एनपीएचएच	3,270.60	725	23.71	1,200	39.25	15.54
			चावल		2,610.42	1,000	26.10	1,500	39.16	13.06
			आटा		3,515.40	800	28.12	1,300	45.70	17.58
12.	उधमपुर	अक्टूबर 2016	चावल	एनपीएचएच	2,720.58	1,000	27.21	1,500	40.81	13.60
			आटा		4,929.82	800	39.44	1,300	64.09	24.65
			गेहूं		1,510.84	725	10.95	1,200	18.13	7.18
			चावल	एमएमएसए फ़ईएस	1,877.61	1,200	22.53	1,500	28.16	5.63
			आटा		1,773.22	800	14.19	1,300	23.05	8.86
			गेहूं		406.53	725	2.95	1,200	4.88	1.93
योग					1,38,117.77		1,345.78		2,031.20	685.42

(स्रोत: संबंधित सहायक निदेशकों द्वारा अनुरक्षित इशू रजिस्टर और ऑफ-टेक स्टेटमेंट)

परिशिष्ट-3.11.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.11; पृष्ठ: 140)

वेतन बकायों तथा अमान्य भत्तों के अधिक भुगतान के समय-वार ब्योरों को दर्शाता विवरण

(₹ राशि में)

क्रम सं.	डीडीओ का नाम	कर्मचारियों के नाम	अवधि	वसूली योग्य राशि	की गई वसूली	शेष
वेतन भत्तों का अधिक भुगतान						
1.	अपर एसपी श्रीनगर	बशीर अहमद सं. 655/एस	अगस्त 2009 से सितंबर 2017	4,16,740	2,72,000	1,44,740
2.	एसएसपी कुलगाम	तारिक अहमद सं. 668/केजीएम (वर्तमान में एसएसपी अनंतनाग के अंतर्गत तैनात)	मार्च 2008 से अक्टूबर 2018	5,76,041	5,76,041	शून्य
3.	एसएसपी कुलगाम	फजौल रहमान सं. 793/ केजीएम (वर्तमान में एसएसपी बांडीपोरा के अंतर्गत तैनात)	जून 2012 से नवंबर 2018	2,61,072	40,000	2,21,072
4.	एसएसपी कुलगाम	मुश्ताक अहमद सं. 1024/ केजीएम (वर्तमान में एसएसपी अवन्तिपोरा के अंतर्गत तैनात)	जुलाई 2011 से सितंबर 2018	4,53,875	90,000	3,63,875
5.	एसएसपी कुलगाम	निसार अहमद सं.1035/ केजीएम (वर्तमान में एसएसपी बडगाम के अंतर्गत तैनात)	अप्रैल 2002 से फरवरी 2018	5,96,318	1,15,000	4,81,318
6.	एसएसपी कुलगाम	सजद अहमद सं.1034/ केजीएम (वर्तमान में एसएसपी श्रीनगर के अंतर्गत तैनात)	दिसंबर 2011 से अक्टूबर 2018	5,55,463	81,000	4,74,463

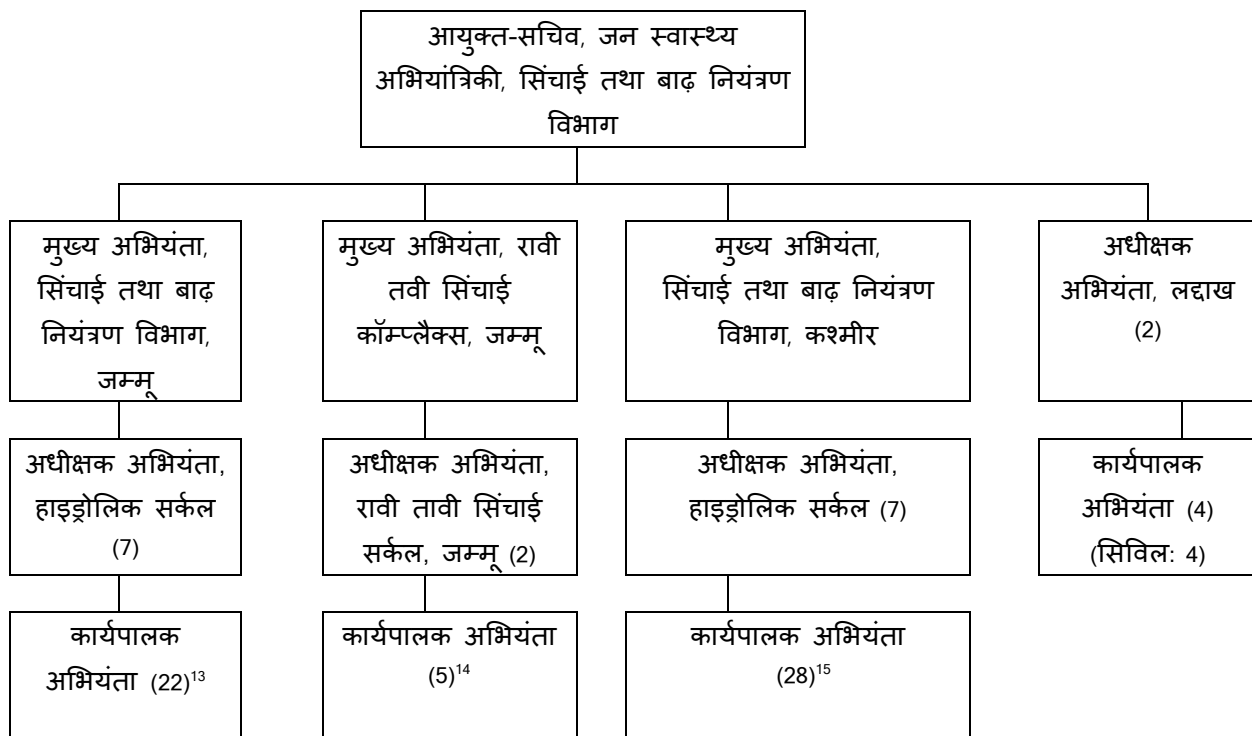
क्रम सं.	डीडीओ का नाम	कर्मचारियों के नाम	अवधि	वसूली योग्य राशि	की गई वसूली	शेष
वेतन भत्तों का अधिक भुगतान						
7.	एसएसपी कुलगाम	रेयाज़ अहमद सं. 1036/ केजीएम (वर्तमान में एसएसपी गांदरबल के अंतर्गत तैनात)	दिसंबर 2011 से नवंबर 2018	4,50,782	45,000	4,05,782
	योग			33,10,291	12,19,041	20,91,250
अमान्य भत्तें						
8.	एसएसपी, सीआईडी, सीआईके, श्रीनगर	अमान्य राशन मनी भत्ता (140 कर्मचारी)	सितंबर 2009 से फरवरी 2015	12,87,600	8,14,100	4,73,500
	कुल योग			45,97,891	20,33,141	25,64,750

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट-3.12.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.12.1; पृष्ठ: 141)

सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग का संगठनात्मक चार्ट



(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

¹³ सिविल: 15; यांत्रिक: 3 तथा बाढ़ नियंत्रण: 4

¹⁴ सिविल: 3 तथा यांत्रिक: 2

¹⁵ सिविल: 18; यांत्रिक: 6 तथा बाढ़ नियंत्रण: 4

परिशिष्ट-3.12.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.12.2.1; पृष्ठ: 143)

प्रति हेक्टेयर एक लाख से अधिक विकास लागत वाली 28 योजनाओं के ब्योरे को दर्शाता विवरण

क्रम सं.	योजना का नाम	डिवीजन का नाम	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	मार्च 2018 तक किया गया व्यय (₹ लाख में)	प्रति हेक्टेयर विकास लागत (₹ लाख में)	आरंभ करने का वर्ष	पूर्ण करने का नियत वर्ष
1.	एलआईएस नागर गुसैन	सिंचाई डिवीजन, अखनूर	96.00	95.70	1.47	2011-12	2013-14
2.	एलआईएस चोकी और चोरा		550.00	549.78	1.45	2008-09	2010-11
3.	एलआईएस कोट-II		150.00	150.00	1.50	2011-12	2013-14
4.	एलआईएस गंगाल		113.00	113.00	1.50	2011-12	2013-14
5.	एलआईएस सिधरा (दन्ना)		135.00	128.98	1.50	2011-12	2013-14
6.	एलआईएस समोह चपरियाल		798.00	729.05	1.25	2008-09	2010-11
7.	मैट अनसू खुल का निर्माण	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, उधमपुर	63.11	63.11	1.26	2011-12	2013-14
8.	बाना तालाब से नाला बाड़ी का निर्माण		84.94	82.65	1.06	2011-12	2014-15
9.	जोगानी नाला से चौकी तक खुल का निर्माण		99.90	99.90	1.11	2011-12	2014-15
10.	कटवाल्ड खुल का निर्माण		81.21	81.21	1.28	2011-12	2014-15
11.	हंसा खुल पर चैक बांध का निर्माण		541.00	203.37	1.50	2011-12	2014-15
12.	थंगर खुल का निर्माण		111.00	75.95	1.00	2011-12	2014-15
13.	एलआईएस डब्बर पोथा का पुनःप्रतिरूपण/विस्तार	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, नौशेरा	129.77	128.47	1.02	2009-10	2012-13
14.	एलआईएस राजल के अंतर्गत जल की वृद्धि के लिए गुरुत्वीय फीडर का निर्माण		1,750.00	1,784.33	1.23	2006-07	2011-12
15.	एलआईएस खलसियान		129.00	129.00	2.35	2011-12	2013-14
16.	एलआईएस बेरी पट्टन		5,108.00	1,249.93	3.01	2011-12	2015-16
17.	सेरी खुल	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, राजौरी	58.98	45.25	1.07	2011-12	2013-14
18.	शुंगरी खुल		105.00	65.85	1.15	2011-12	2013-14
19.	लाउंडी खुल		95.42	62.88	1.25	2011-12	2013-14

क्रम सं.	योजना का नाम	डिवीजन का नाम	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	मार्च 2018 तक किया गया व्यय (₹ लाख में)	प्रति हेक्टेयर विकास लागत (₹ लाख में)	आरंभ करने का वर्ष	पूर्ण करने का नियत वर्ष
20.	एलआईएस धेरी धारा	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, राजौरी	119.00	118.89	1.58	2008-09	2010-11
21.	रकीबन खुल	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, राजौरी	336.00	149.88	1.56	2011-12	2013-14
22.	पेरी डंडेवली खुल		162.74	114.59	1.29	2011-12	2013-14
23.	खंडाफेर खुल		79.05	48.12	1.36	2011-12	2013-14
24.	तरकुला खोड़ मोंग खुल		198.92	127.44	1.17	2011-12	2013-14
25.	नव खुल का निर्माण	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, बडगाम	893.77	73.20	1.06	2013-14	2015-16
26.	लिफ्ट सिंचाई योजना डुलांजा	हाइड्रोलिक डिवीजन, उरी	179.50	119.58	1.31	2011-12	2013-14
27.	पेठान जमींदारी खुल की पुनःप्रतिरूपण	सिंचाई डिवीजन, अनंतनाग	274.00	307.21	1.49	2011-12	2012-13
28.	वीरवार खुल का पुनःप्रतिरूपण		927.00	575.47	1.92	2011-12	2012-13
योग			13,369.31	7,472.79			

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट-3.12.3

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.12.5; पृष्ठ: 151)

चयनित डिवीजनों में अधिकतम सिंचाई सामर्थ्य, सृजित सिंचाई सामर्थ्य तथा प्रयुक्त सिंचाई सामर्थ्य को दर्शाता विवरण

(हेक्टर में)

क्रम सं.	डिवीजन का नाम	अधिकतम सिंचाई सामर्थ्य (यूआईपी)	निर्मित सिंचाई सामर्थ्य (आईपीसी)	प्रयुक्त सिंचाई सामर्थ्य (आईपीयू)	प्रतिशत प्राप्ति	
					यूआईपी के संदर्भ सहित सिंचाई सामर्थ्य का निर्माण	आईपीसी के संदर्भ सहित सिंचाई सामर्थ्य का उपयोग
1.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, राजौरी	6,825	1,635	1,188	24	73
2.	सिंचाई डिवीजन, अखनूर	4,184	1,315	50	31	4
3.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, नौशेरा	7,885	3,415	852	43	25
4.	सिंचाई डिवीजन, कठुआ	14,650	3,759	1,722	26	46
5.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, उधमपुर	4,328	953	389	22	41
6.	सिंचाई डिवीजन- I जम्मू	59,478	54,713	54,675	92	100
7.	सिंचाई डिवीजन- II जम्मू	640	290	255	45	88
8.	रवि तवी सिंचाई कॉम्प्लेक्स जम्मू	15,016	13,240	11,480	88	87
9.	नलकूप सिंचाई डिवीजन जम्मू	2,607	1,344	542	52	40
10.	सिंचाई डिवीजन, अनंतनाग	14,495	5,548	4,068	38	73
11.	सिंचाई डिवीजन, बारामूला	13,474	2,086	2,086	15	100
12.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, सोपोर	6,181	1,105	1,105	18	100
13.	फिरोज़पुर बेसिन सिंचाई डिवीजन, तंगमर्ग	9,698	8,015	8,015	83	100
14.	हाइड्रोलिक डिवीजन, उरी	4,063	470	470	12	100
15.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, बडगाम	16,837	9,720	8,672	58	89
16.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, हंदवाड़ा	1,325	50	50	4	100
17.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, कुपवाड़ा	7,685	2,000	628	26	31
योग		1,89,371	1,09,658	96,247	58	88

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट-3.12.4

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.12.8.1; पृष्ठ: 156)

पूर्ण होने वाले निर्माण कार्य, वास्तविक पूर्ण निर्माण कार्य तथा देरी हेतु कारणों के विभिन्न चरणों को दर्शाता विवरण

विवरण	लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के नाम	
	बेरी पट्टन	अंबारण-II
अनुमानित लागत	₹51.08 करोड़	₹4.45 करोड़
पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	2015-16	2009-10
जारी की गई निधियाँ	₹17.71 ¹⁶ करोड़	₹4.45 करोड़
व्यय	₹17.71 ¹⁷ करोड़	₹4.45 करोड़
सिविल निर्माण कार्य		
क्रियान्वयित किया जाने वाला	मुख्य कार्य, मुख्य नहर, शाखाओं आदि का निर्माण।	पंप हाउस, डिलीवरी टैंक, मुख्य चैनल, वितरण प्रणाली आदि का निर्माण।
वास्तविक क्रियान्वयित	केवल 20 प्रतिशत सिविल कार्यों को ही क्रियान्वित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से खुदाई शामिल हैं जैसा कि घटनास्थल पर सत्यापित हुआ।	केवल 60 प्रतिशत सिविल कार्य क्रियान्वित (पंप हाउस प्रगति में, वितरण टैंक पूर्ण, मुख्य चैनल और वितरण प्रणाली आंशिक रूप से पूरा हुआ)।
देरी हेतु कारण	अपर्याप्त निधि	अपर्याप्त फंडिंग। एमआईसीडी, जम्मू द्वारा संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने के कारण परियोजना को संशोधित किया गया। जिसकी मंजूरी प्रतीक्षित है।
विद्युत यांत्रिक कार्य		
क्रियान्वयित किया जाने वाला	पम्पिंग मशीनरी की स्थापना, संबंधित कार्यों के साथ राइजिंग मेन और विद्युत उप-स्टेशन का निर्माण।	पम्पिंग मशीनरी की स्थापना, संबंधित कार्यों के साथ-साथ राइजिंग मेन और इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन का निर्माण।
वास्तविक रूप से क्रियान्वित	कोई यांत्रिक कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन का काम पूरा हो चुका है।	राइजिंग मेन और पंपिंग मशीनरी की केवल खरीद की गई, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन का काम पूरा किया गया है।
देरी हेतु कारण	सिविल डिवीजन द्वारा पंप रूम बिल्डिंग का निर्माण न होना। स्टेज फर्स्ट पंप रूम और कैनाल सेक्शन आरडी: 0-5410एम के काम को निविदा आधार पर लिया गया था। हालांकि 10 से 45 प्रतिशत काम पूरा करने के बाद छोड़ दिया गया।	विद्युत यांत्रिक कार्यों के निष्पादन के लिए निधि प्रतीक्षित।

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

¹⁶ 2018-19 के दौरान जारी ₹5.21 करोड़ के साथ

¹⁷ सितंबर 2019 तक व्यय

परिशिष्ट-3.12.5

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.12.8.2; पृष्ठ: 158)

आठ सैंपल डिवीजनों में निष्क्रिय पड़ी मशीनरी के योजना वार ब्योरे दर्शाता विवरण

क्रम सं.	लिफ्ट सिंचाई योजना का नाम	डिवीजन का नाम	मशीनरी और संबद्ध सामाग्री का विवरण	लागत (₹ लाख में)	अवधि जिससे प्रयोग में नहीं
1.	राजपुरा	सिंचाई डिवीजन, अखनूर	(i) एचसी पंप, हेड मोटर, केवी स्टार्टर आदि और मेन रिफ्लेक्स वाल्व आदि।	24.60	सितंबर 2010
2.	नागर गुसैन		मोटर और स्टार्टर, स्लुइस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व, फुट वैल्यू के साथ एचसी पंप	10.55	जनवरी 2014 से सितंबर 2014
3.	सिधरा धाना		मोटर और स्टार्टर, स्लुइस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व और फुट वाल्व के साथ एचसी पंप	10.52	जनवरी 2014 से सितंबर 2014
4.	अंबारन-II		मोटर, स्टार्टर, स्लुइस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व, फुट वाल्व आदि के साथ एचसी पंप	100.93	अक्टूबर 2014
5.	नूड बिहारा		फुट वाल्व	0.68	सितंबर 2014 (2016-17 में योजना पूर्ण)
6.	धेरी धारा	सिंचाई और बाढ़	एमआरवी	0.48	जून 2013
7.	रकीबन	नियंत्रण डिवीजन, राजौरी	मोटर और स्टार्टर, स्लुइस वाल्व के साथ एचसी पंप	8.70	जनवरी 2014 से सितंबर 2014
8.	ज़िंदा पीर	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, नौशेरा	मोटर और स्टार्टर और फुट वाल्व के साथ एचसी पंप	1.67	जनवरी 2014 से सितंबर 2014
9.	नबरी बरोटा	सिंचाई डिवीजन, कठुआ	मोटर और स्टार्टर के साथ स्लुइस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व और फुट वाल्व के साथ एचसी पंप	45.07	जनवरी 2014 से सितंबर 2014
10.	लोअर राजवालता		मोटर और स्टार्टर, स्लुइस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व और फुट वाल्व के साथ एचसी पंप	40.38	जनवरी 2014 से सितंबर 2014
9.	नबरी बरोटा	सिंचाई डिवीजन, कठुआ	मोटर और स्टार्टर के साथ स्लुइस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व और फुट वाल्व के साथ एचसी पंप	45.07	जनवरी 2014 से सितंबर 2014
10.	लोअर राजवालता		मोटर और स्टार्टर, स्लुइस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व और फुट वाल्व के साथ एचसी पंप	40.38	जनवरी 2014 से सितंबर 2014

क्रम सं	लिफ्ट सिंचाई योजना का नाम	डिवीजन का नाम	मशीनरी और संबद्ध सामाग्री का विवरण	लागत (₹ लाख में)	अवधि जिससे प्रयोग में नहीं
11.	मांडयारी	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन सोपोर	पम्पिंग उपकरण, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन गैन्ट्री, मॉड्यूलर कंट्रोल पेनल्टी एनआरवी 350 एमएम 130 एम्पीयर स्टेबलाइजर आदि	40.31	मई 2012 से जनवरी 2015
12.	बर्न हंजीवीरा		पम्पिंग उपकरण, प्राइमिंग पंप, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन गैन्ट्री, मॉड्यूलर कंट्रोल पेनल्टी एनआरवी 350 एमएम आदि	34.98	जनवरी 2014 से दिसंबर 2014
13.	अहमदपोरा कौंगामधारा		यांत्रिक कार्य वाल्व, एमएस पाइप, एनआरवी फ्लैंगेस, पावर केबल, 300 एचपी एटीएस स्टार्टर आदि।	146.22	मई 2012 से सितंबर 2015
14.	आदिपोरा		10 क्यूसेक पंपिंग उपकरण, 120 वर्ग मिमी केबल, रिफ्लेक्स वाल्व आदि।	43.57	सितंबर 2014 से मार्च 2015
15.	चोटीपोरा	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, बारामूला	70 वर्ग एमएम ए1 केबल, सीयू केबल, रिफ्लेक्स वाल्व, मॉड्यूलर कंट्रोल पैनल आदि।	8.94	अक्टूबर 2014 से मार्च 2015
16.	दुलांजा	हाइड्रोलिक डिवीजन उरी	300 केवीए वोल्टेज स्टेबलाइजर, वीटी पंप, मुख्य नियंत्रण कक्ष आदि।	80.22	नवंबर 2011 से मार्च 2012
17.	बोंगा सलामाबाद		100 केवी वोल्टेज स्टेबलाइजर, 125 डीआईए का राइजिंग मेन , स्टील के खंभे आदि	15.81	अप्रैल 2012 से फरवरी 2015
18.	बुधरेशी	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, हंदवाड़ा	300 केवीए वोल्टेज स्टेबलाइजर, मुख्य वितरण चैनल, राइजिंग मेन के लिए 800 मिमी पाइप, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन आदि।	51.16	सितंबर 2009 से फरवरी 2014
19.	वादिपोरा		इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 1 क्यूसेक क्षमता वाली क्षैतिज पंप	4.90	2016
योग				669.69	

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट-3.15.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.15; पृष्ठ: 164)

अनुमानित लागत, आबंटित/ निर्मोचित निधि, किया गया व्यय, देय पर्यवेक्षण प्रभार, बकाया तथा वसूल किए गए पर्यवेक्षण प्रभारों के कार्य-वार ब्योरे दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	आरंभ की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	अनुमानित लागत	जारी की गई निधियाँ	जनवरी 2018 तक व्यय	पर्यवेक्षण प्रभार	वसूल किए गए पर्यवेक्षण प्रभार	बकाया शेष	फ़र्म जिससे वसूली की जानी है	कार्य की वर्तमान स्थिति
1.	रैटल पावर हाउस, किशतवाड़ के लिए 10 एमवीए, 33 केवी रिसेविंग स्टेशन का निर्माण	नवंबर 2012	दिसंबर 2016	205.69	205.69	499.22	47.43	15.76	31.67	मैसर्स जीवीके पावर और इन्फ्रा लिमिटेड गुड़गाँव	पूर्ण
2.	निर्माणाधीन 132/33 केवी ग्रिड स्टेशन किशतवाड़ से रैटल पावर हाउस किशतवाड़ तक 12,050 किलोमीटर लंबी 33 केवी लाइन बिछाना	मई 2012	मई 2013	171.50	171.50						
	सामग्री और श्रम के मूल्य वृद्धि के लिए क्रम सं. 1 & 2 पर 20% प्रावधान			75.44	75.44						
3.	रिसेविंग स्टेशन ठठरी को 6.3 एमवीए से 10 एमवीए तक बढ़ाना	अक्टूबर 2012	मार्च 2013	18.97	18.97						

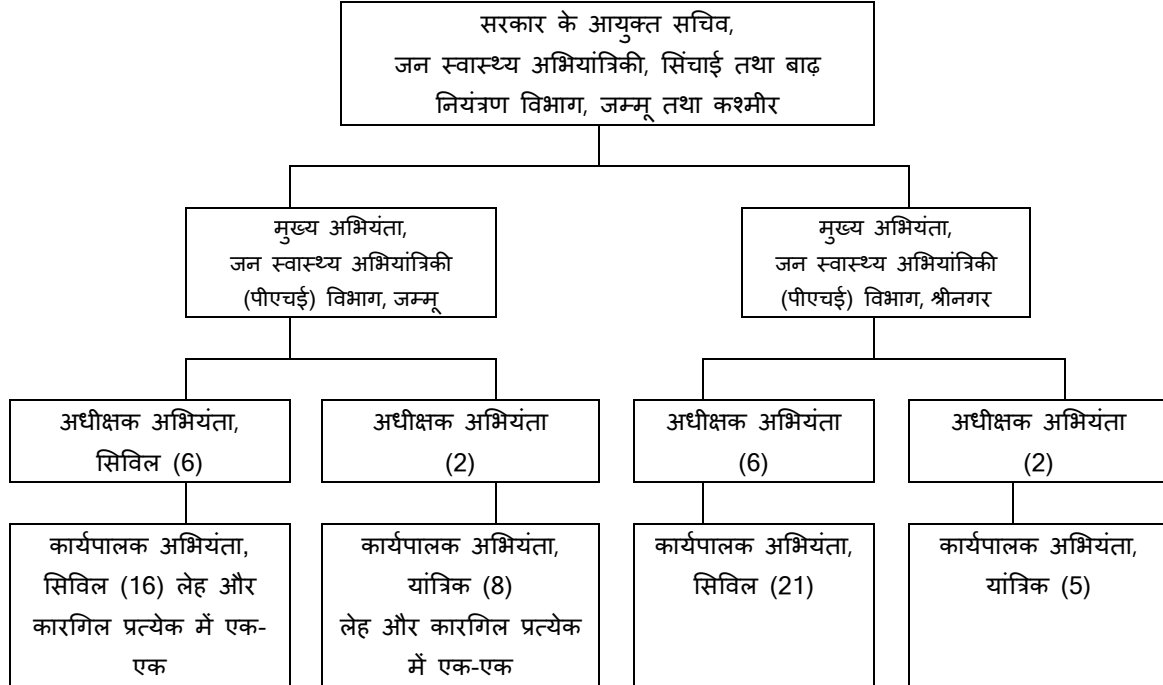
क्र. सं.	कार्य का नाम	आरंभ की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	अनुमानित लागत	जारी की गई निधियाँ	जनवरी 2018 तक व्यय	पर्यवेक्षण प्रभार	वसूल किए गए पर्यवेक्षण प्रभार	बकाया शेष	फ़र्म जिससे वसूली की जानी है	कार्य की वर्तमान स्थिति
4.	ईएम और आरई डिवीजन किशतवाड़ के माध्यम से रेटल पावर हाउस किशतवाड़ के लिए अलग से 7 किमी लंबी 11 केवी फीडर प्रदान करना	अक्टूबर 2012	अप्रैल 2013	41.63	41.63						
5.	3.15 एमवीए, 33/11 केवी रिसेविंग स्टेशन एलकेएचईपी परियोजना ठठरी का निर्माण	मई 2015	अगस्त 2015	195.47	25.00	21.93	2.08	1.71	0.37	मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	अपूर्ण
	योग			708.70	538.23	521.15	49.51	17.47	32.04		

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट-3.16.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.16.1; पृष्ठ: 166)

पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वीकृति हेतु अंगीकृत प्रक्रिया तथा पीएचई विभाग का संगठनात्मक चार्ट



पंजीकरण प्रमाण पत्र के स्वीकृति हेतु अंगीकृत प्रक्रिया

भू-जल की निकासी के लिए बोर/ ट्यूबवेल की स्थापना के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) की स्वीकृति के लिए आवेदन मुख्य अभियंता पीएचई विभाग के कार्यालय में प्राप्त होता है। मुख्य अभियंता इसे अधीक्षक अभियंता (एसई), हाइड्रोलिक और मैकेनिकल सर्कल की टिप्पणियों और अनुशंसाओं के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए आगे भेजता है। संबंधित सिविल और मैकेनिकल डिवीजन से रिपोर्ट और अनुशंसायें प्राप्त होने पर एसई हाइड्रोलिक और एसई मैकेनिकल अपनी रिपोर्ट और अनुशंसा के साथ मामले को फिर से मुख्य अभियंता पीएचई विभाग को प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट और अनुशंसा मिलने के बाद मुख्य अभियंता या तो आरसी को अस्वीकार कर देते हैं या उपयोगकर्ता को भू-जल के निष्कर्षण और दोहन के लिए कुछ शर्तों के अधीन स्वीकार करते हैं, जिसके लिए संबंधित डिवीजन के डिवीजनल प्रमुख (कार्यकारी अभियंता) द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, लाइसेंसधारी से पानी के उपयोग के शुल्क की मांग और वसूली भी कार्यकारी अभियंता की जिम्मेदारियों में से एक है।

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट-3.16.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.16.3; पृष्ठ: 168)

2013 से 2016 की अवधि के दौरान राज्य (जम्मू/ कश्मीर) के दो डिवीजनों के कुओं में शीतकाल उपरांत और मानसून उपरांत भू-जल स्तर (जीडबल्यूएल) का मौसमी और वार्षिक वर्षा में उतार-चढ़ाव

जीडबल्यूएल में वृद्धि/ गिरावट	2013			2014			2015			2016		
	कुओं की संख्या- दर्शाते हुए											
	जीडबल्यूएल में वृद्धि	जीडबल्यूएल में गिरावट	योग	जीडबल्यूएल में वृद्धि	जीडबल्यूएल में गिरावट	योग	जीडबल्यूएल में वृद्धि	जीडबल्यूएल में गिरावट	योग	जीडबल्यूएल में वृद्धि	जीडबल्यूएल में गिरावट	योग
जम्मू डिवीजन जहां मानसून के बाद भू-जल स्तर बढ़ता है मानसून उपरांत (मई की तुलना में नवंबर)												
0-2 मी	121	08	129	136	30	166	107	71	178	136	30	166
2-4 मी	37	02	39	22	01	23	16	04	20	38	04	42
>4 मी	29	00	29	13	01	14	8	04	12	15	00	15
कुओं की कुल संख्या	187	10	197	171	32	203	131	79	210	189	34	223
वर्ष के दौरान कुल कुओं का प्रतिशत	95	05	एनए	84	16	एनए	62	38	एनए	85	15	एनए
कश्मीर डिवीजन जहां भूजल स्तर सर्दियों के बाद बढ़ता है सर्दियों के बाद (नवंबर की तुलना में मई)												
0-2 मी	15	02	17	18	00	18	12	02	14	06	08	14
2-4 मी	04	01	05	08	00	08	02	02	04	04	00	04
>4 मी	04	01	05	02	00	02	04	00	04	01	02	03
कुओं की कुल संख्या	23	04	27	28	00	28	18	04	22	11	10	21
वर्ष के दौरान कुल कुओं का प्रतिशत	85	15	एनए	100	शून्य	एनए	82	18	एनए	52	48	एनए

(स्रोत: वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए सीजीडबल्यूबी द्वारा तैयार ग्राउंड वॉटर इंडेक्स बुक)

2013 से 2016 की अवधि के दौरान सामान्य से विचलन के साथ राज्य में मौसमी और वार्षिक वर्षा गिरावट (मिमी)										
वर्ष	शीतकाल		मॉनसून-पूर्व		मानसून		मानसून-पश्चात		वार्षिक	
	वर्षा (एमएम)	सामान्य वृद्धि(+)/ गिरावट(-) से प्रतिशत विचलन	वर्षा (एमएम)	सामान्य वृद्धि(+)/ गिरावट(-) से प्रतिशत विचलन	वर्षा (एमएम)	सामान्य वृद्धि(+)/ गिरावट(-) से प्रतिशत विचलन	वर्षा (एमएम)	सामान्य वृद्धि(+)/ गिरावट(-) से प्रतिशत विचलन	वर्षा (एमएम)	सामान्य वृद्धि(+)/ गिरावट(-) से प्रतिशत विचलन
2013	257.1	(+) 21	189.4	(-) 42	651.9	(+) 22	95.4	(-) 28	1193.8	(-) 1
2014	195.0	(-) 8	395.0	(+) 21	633.4	(+) 18	55.0	(-) 58	1278.4	(+) 6
2015	215.1	(+) 1	579.3	(+) 78	613.9	(+) 15	164.4	(+) 25	1572.7	(+) 30
2016	78.8	(-) 63	331.8	(+) 2	482.7	(-) 10	9.4	(-) 93	902.7	(-) 25

(स्रोत: हाइड्रोमेट डिवीजन, भारत मौसम विभाग द्वारा वर्षा के आंकड़ों पर रिपोर्ट)

परिशिष्ट-3.17.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.17; पृष्ठ: 184)

जुलाई 2016 के परे मुख्य अभियंता, पीएचई जम्मू के कार्यालय में स्टाफ का निरंतर संयोजन दर्शाता विवरण

क्रम सं.	नाम सुश्री/ श्री	पदनाम	संयोजन की अवधि			जुलाई 2016 से परे संयोजन के पूर्ण महीनों की संख्या	अगस्त 2016 से मई 2016 के दौरान भुगतान किया गया वेतन (₹ में)
			से	तक	पूर्ण महीनों की संख्या		
1.	रजिन्दर कुमार शर्मा	ईई	19.05.2016	12.12.2017	18	16	16,41,884
2.	रवि कान्त शर्मा	ईई	14.12.2016	31.07.2017	07	07	8,91,265
3.	राजेश कुमार गंडोत्रा	एईई	01.02.2016	17.09.2016	07	01	87,569
4.	गुरनाम सिंह	एईई	28.02.2015	मई 2018	39	22	18,23,787
5.	विजय कुमार शर्मा	एईई	25.04.2016	16.10.2017	17	14	12,36,527
6.	गोपाल कृष्ण गुप्ता	एईई	12.07.2016	मई 2018	22	22	1,50,23,808
7.	अनिल गुप्ता	एईई	22.09.2016	16.09.2017	11	11	9,01,304
8.	सुनील शर्मा	एईई	10.09.2016	मई 2018	20	20	32,48,824
9.	अजित कुमार	एईई	03.01.2017	27.11.2017	10	10	11,00,543
10.	सुनील सेठ	एईई	19.05.2016	20.09.2017	15	13	9,64,557
11.	नरिंदर कुमार सपोलिया	एईई	03.02.2017	21.04.2017	02	02	2,69,317
12.	करमवीर सिंह स्लाठिया	एई	02.02.2016	30.09.2017	20	14	5,51,103
13.	विजय कुमार चौधरी	एई	31.10.2017	मई 2018	19	19	30,18,994
14.	सुभाष चंद्र शर्मा	एई	09.11.2016	31.11.2017	12	12	14,39,643
15.	हरि बूषण	एईई	29.05.2012	30.06.2017	61	11	3,41,583
16.	सिसर खजूरिया	एईई	29.03.2017	मई 2018	14	14	12,19,692

क्रम सं.	नाम सुश्री/ श्री	पदनाम	संयोजन की अवधि			जुलाई 2016 से परे संयोजन के पूर्ण महीनों की संख्या	अगस्त 2016 से मई 2016 के दौरान भुगतान किया गया वेतन (₹ में)
			से	तक	पूर्ण महीनों की संख्या		
17.	सगीर हुसैन मलिक	एईई	29.06.2017	मई 2018	11	11	16,79,758
18.	अनिल शर्मा	एईई	22.04.2017	17.10.2017	05	05	5,11,693
19.	ब्रिज मोहन	एईई	21.11.2017	मई 2018	06	06	4,33,424
20.	राजिन्दर सिंह	एई	08.08.2017	08.01.2018	04	04	4,55,380
	योग						3,68,40,655

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

(नोट: ईई: कार्यपालक अभियंता, एईई: सहायक कार्यपालक अभियंता, तथा एई: सहायक अभियंता)

परिशिष्ट-3.24.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.24; पृष्ठ: 196)

राजस्व विभाग में अधिक वेतन और भत्ते तथा की गई वसूलियां दिखाता कार्यालय-वार विवरण

(₹ राशि में)

क्रम सं	डीडीओ का नाम	कर्मचारियों की संख्या	अवधि	एनपीएस अंशदान सहित अधिक आहरित वेतन	वसूली गयी राशि	बकाया राशि
1.	क्षेत्रीय निदेशक, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख, मारज अनंतनाग	38	जुलाई 2014 से दिसंबर 2017	12,82,272	12,82,272	शून्य
2.	क्षेत्रीय निदेशक, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख, बारामूला	70	जुलाई 2014 से फरवरी 2018	24,92,840	18,22,184 (मार्च 2019 तक)	6,70,656
3.	क्षेत्रीय निदेशक, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख, श्रीनगर	43	जुलाई 2014 से मार्च 2018	15,70,059	10,32,000 (मार्च 2019 तक)	5,38,059
4.	तहसीलदार कुलगाम	23	जुलाई 2014 से मार्च 2018	8,39,799	4,43,049 (जुलाई 2018 तक)	3,96,750
5.	तहसीलदार अनंतनाग	7	जुलाई 2014 से दिसम्बर 2017	2,36,208	2,15,544 (अप्रैल 2019 तक)	20,664
	योग	181		64,21,178	47,95,049	16,26,129

(स्रोत: वेतन तथा वेतन पंजिका)